

गोली और बम रोकने से रहे, आतंकियों से डरते नहीं

अग्नि-5 मिसाइल होगी और घातक, बंकर भेदने में सक्षम

नई दिल्ली (एजेंसी)। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भयावह आतंकवादी हमले का असर इस साल अमरनाथ यात्रा पर पड़ने की आशंका थी। हालांकि, इसे दरकिनार करते हुए देश के विभिन्न भागों से सैकड़ों तीर्थयात्री पहले दिन पंजीकरण केंद्र पर कतारों में खड़े दिखाई दिए। 11वीं बार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे मुंबई निवासी दिवाकर कदम ने कहा, गोली और बम हमें बाबा बर्फानी के दर्शन करने से नहीं रोक सकते। जम्मू रेलवे स्टेशन के निकट सरस्वती धाम पंजीकरण केंद्र पर रजिस्ट्रेशन के पहले दिन लोगों की भीड़ देखी गई। वहां उपस्थित कई लोगों ने बढ़ती भीड़ को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को करारा जवाब बताया। आतंकियों ने 22 अप्रैल को किए गए



हमले में विशेष धर्म के लोगों की पहचान करके पहलगाम में 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बम बम बोले और जय बाबा बर्फानी के नारों के बीच

● अमरनाथ तीर्थयात्रियों का दम, चुन लिया पहलगाम मार्ग

लिए पहलगाम मार्ग से अमरनाथ की तीर्थयात्रा कर रहे हैं। दिवाकर कदम ने कहा, हम बहुत उत्साहित हैं। हमारे 26 सदस्यों का समूह बेहद खुश है। हम अमरनाथ जी के दर्शन करने वाले पहले जत्थे का हिस्सा बनना चाहते हैं। हमें कोई डर नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, अमरनाथ यात्रा के लिए देशभर के लोगों का उत्साह कम नहीं हो सकता। हर कोई आएगा और दर्शन करेगा। दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर की 38 दिवसीय तीर्थयात्रा तीन जुलाई को दो मार्गों से शुरू होगी। इसमें अनंतनाग जिले में पारंपरिक पहलगाम मार्ग है।

● डीआरडीओ 2 वर्जन पर कर रहा है काम, जबरदस्त तैयारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत बंकर-भेदी क्षमता वाली नई हार्ड पावर की मिसाइलों को तैयार कर रहा है, जो बेहद सुरक्षित माने जाने वाले भूमिगत ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम होंगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन अग्नि-5 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के नए वर्जन पर काम कर रहा है। यह मिसाइल कंक्रीट की परतों के नीचे 80 से 100 मीटर तक आसानी से पहुंच सकती है। अमेरिका ने हाल ही में ईरान के परमाणु स्थलों को



भारी बंकर-भेदी बमों का इस्तेमाल करके ध्वस्त कर दिया था। कहा जा रहा है कि इसे ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ भी कुछ ऐसी ही ताकत हासिल करना चाहता है। मौजूदा अग्नि-5 मिसाइल की रेंज 5 हजार किलोमीटर से अधिक है।

अब पहली नौकरी मिलते ही खाते में पैसे डालेगी सरकार

केन्द्रीय कैबिनेट ने तीन बड़ी योजनाओं को दी मंजूरी



नई दिल्ली (एजेंसी)। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को युवाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। केन्द्रीय कैबिनेट ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है जिसका लाभ दो चरण में मिलेगा। पहले चरण में में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को अधिकतम 15 लाख रुपये दिए जाएंगे। क्रिस्त नौकरी लगने के



छठे और 12वां महीने में मिलेगी। वहीं दूसरे चरण में 3000 रुपये प्रति महीने प्रदान किए जाएंगे। पूरी योजना विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित होगी। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार इस योजना में कुल 1.07 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसका मकसद सभी क्षेत्रों में रोजगार क्षमता बढ़ाना है।

कृषि उत्पादों पर अमरीका के आगे नहीं झुकेगा भारत

राष्ट्रपति ट्रंप को आईना दिखाने की तैयारी, 8 दिन बचे

वाशिंगटन (एजेंसी)। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत फिलहाल गतिरोध की स्थिति में पहुंच गई है।



इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा निर्धारित 8 जुलाई की समयसीमा भी तेजी से नजदीक आ रही है। यदि दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाता है तो इस तारीख के बाद अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 26 फीसदी जवाबी टैरिफ लागू करने की संभावना है। भारत के मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में

भारतीय दल वाशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों के साथ चर्चा के लिए रुका हुआ है, अमेरिका चाहता है कि भारत

और आगे बढ़ने की संभावना बेहद कम है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका चाहता है कि भारत

नरेंद्र मोदी सरकार इस मांग को मानने में हिचक रही है, क्योंकि इन उत्पादों से देश के लाखों छोटे किसान जुड़े हुए हैं। राजनीतिक रूप से भी कृषि क्षेत्र में रियायत देना सरकार के लिए जोखिम भरा हो सकता है। मोदी सरकार का कहना है कि इन उत्पादों पर निर्भर छोटे किसानों के हितों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता है। इसके अलावा, डेयरी और आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों पर भारत का रुख सख्त है, क्योंकि यह किसानों की आजीविका और घरेलू राजनीतिक संवेदनशीलताओं से जुड़ा हुआ है।

मक्का, सोयाबीन, डेयरी उत्पाद, सेब, और अन्य फलों एवं मेवों पर आयात शुल्क कम करें। लेकिन

तेलंगाना विस्फोट में बढ़ गई मृतकों की संख्या

● बढ़कर 36 पहुंची, मलबे में दबे मिले कई शव

हैदराबाद (एजेंसी)। तेलंगाना के पाशमायलायम में सिगाची इंडस्ट्रीज के फार्मा प्लांट में हुए विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी

दी। उन्होंने बताया कि मलबे को हटाने के दौरान कई शव मिले। जिला पुलिस अधीक्षक परितोष पंकज ने बताया, 'मलबे से अब तक 31 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 5 लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बचाव अभियान का अंतिम चरण अभी भी जारी है।' मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने दुर्घटना स्थल का दौरा



किया, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री सी. दामोदर राजनरसिम्हा ने बताया। यह घातक हादसा सोमवार को हुआ, जिसके पीछे संदिग्ध कारण रासायनिक प्रतिक्रिया माना जा रहा है। सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक फार्मास्युटिकल कंपनी है। स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजा नरसिम्हा ने बताया कि जब विस्फोट हुआ तब संयंत्र में लगभग 90



लोग काम कर रहे थे। विस्फोट कथित तौर पर संदिग्ध रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण हुआ, जिससे आग भी लग गई।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कुछ श्रमिक लगभग 100 मीटर से ज्यादा दूर जाकर गिरे।

कर्नाटक में डीके की हार, लॉबिंग चली गई बेकार

● बगल में बिठाकर बोले सुरजेवाला-सीएम नहीं बदलेगा

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक में बीते कई दिनों से डीके शिवकुमार के समर्थक मांग कर रहे थे कि अब नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। सिद्धारमेया की जगह पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान की ओर से भेजे गए रणदीप



सुरजेवाला ने उन्हें बगल में बिठाकर दावा खारिज कर दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि आपका सवाल है कि क्या कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है तो मेरा जवाब ना मैं है। सुरजेवाला ने कहा, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या कर्नाटक में नेतृत्व बदल रहा है। इस पर मेरी एक ही जवाब है कि नहीं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, कई विधायकों की ओर से लीडरशिप चेंज की मांग की गई है। इस पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मैं अपने विधायकों को सलाह देता हूं कि यदि उन्हें कोई परेशानी है तो फिर मसले को मीडिया में उठाने की बजाय पार्टी फोरम पर बात करें।

सऊदी अरब के विद्यार्थियों ने किया हिंदी में काव्य पाठ

भोपाल। विश्व रंग फाउंडेशन के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय हिंदी केंद्र एवं प्रवासी भारतीय शोध केंद्र रबींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय द्वारा सऊदी अरब की विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए हिंदी काव्य पाठ का ऑनलाइन आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सऊदी अरब के रियाद, खोबर, जिद्दाह, जुबैल, दमाम आदि शहरों के पांच से बाह्र वर्ष के 15 विद्यार्थियों ने हिंदी में अत्यंत जोशीले अंदाज में काव्य की पाठ किया। विद्यार्थियों ने स्वरचित के अलावा भारत के प्रमुख कवियों रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, अटल बिहारी वाजपेई आदि की रचनाएं भी

सुनाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किंग सऊद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र मेहता रहे और अध्यक्षता रबींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं विश्व रंग के निदेशक संतोष चौबे ने की। प्रारंभ में अंतरराष्ट्रीय हिंदी केंद्र के निदेशक डॉ जवाहर कर्णावट ने विश्व रंग फाउंडेशन की गतिविधियों का परिचय दिया। कार्यक्रम का संयोजन सऊदी अरब की हिंदी एवं गुजराती लेखिका श्रीमती आरती परीख ने किया। अंत में विश्व रंग के सचिव संजय सिंह राठौड़ ने आभार माना। इस कार्यक्रम में देश-विदेश के अनेक श्रोता बड़ी संख्या में शामिल हुए।

व्यापार चर्चा और भारत-पाकिस्तान सीजफायर में संबंध नहीं

● जयशंकर बोले-अमेरिकी उपराष्ट्रपति की पीएम से जब बात हुई, मैं भी उसी कमरे में था

वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका दौर पर गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार संबंधी चर्चा और भारत-पाकिस्तान सीजफायर के बीच कोई संबंध नहीं है। न्यूजवीक मेगजिन के सीईओ देव प्रसाद के साथ इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात कही। जयशंकर ने कहा- 9 मई की रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी से बात की थी। मैं भी उस दौरान उसी कमरे में था।

वेंस ने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान भारत पर बड़े हमले की योजना बना रहा है। पीएम मोदी ने इसकी परवाह न करते हुए कहा था- हमले का जवाब दिया जाएगा। विदेश मंत्री ने कहा- अगली सुबह (10 मई)



अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पीएम से संपर्क किया। कहा- पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। इसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव धई से संपर्क किया और सीजफायर की रिक्वेस्ट की थी। दरअसल, 10 मई को भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर की सबसे पहली सूचना अमेरिकी राष्ट्रपति

डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए दी थी। ट्रम्प ने कई मौके पर कहा है कि भारत-पाकिस्तान को व्यापार न करने की धमकी दी थी, इसके बाद दोनों देश सीजफायर के लिए माने। जयशंकर ने कहा- घटनाक्रम उस तरह से नहीं हुआ था। कूटनीति और व्यापार संबंधी चर्चा पूरी तरह से अलग हैं। मुझे लगता है कि व्यापार से जुड़े लोग वही कर रहे हैं जो उन्हें करना

चाहिए, जैसे- नंबर, लाइनों, प्रोडक्ट्स और व्यापार समझौता। वे सभी इसके प्रोफेशनल हैं और फोकस्ड हैं। जयशंकर ने कहा- भारत का रुख साफ है आतंकवादियों को किसी भी तरह से नहीं छोड़ा जाएगा। अब उन्हें प्रॉक्सी को तौर पर नहीं देखा जाएगा। आतंकियों को पालने वाली सरकारों को नहीं बख्शेंगे। चर्चा के दौरान जयशंकर ने कहा कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला सोचा समझा आर्थिक युद्ध था। इसका मकसद कश्मीर में पर्यटन उद्योग को बर्बाद करना था। यह हमला पर्यटन पर हमला था, जो कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आतंकी चाहते थे कि लोग डरें, पर्यटक न आए और घाटी का आर्थिक ढांचा टूट जाए।

आरसीबी ही जिम्मेदार पुलिस नहीं है भगवान

● बेंगलुरु भगदड़ पर आ गई ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट

● कहा-पुलिस के पास अलादीन का चिराग नहीं

बेंगलुरु (एजेंसी)। चित्रास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ केस में ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें एक 14 वर्षीय बच्ची भी शामिल



थी। आदेश में साफ तौर पर कहा गया कि आरसीबी ने पुलिस से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली थी। अचानक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। पुलिसकर्मी भी इंसान हैं, उनके पास अलादीन का चिराग थोड़े है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि आरसीबी ने सोशल मीडिया पर बिना पुलिस की अनुमति के विजय जुलूस का आमंत्रण पोस्ट कर दिया, जिससे भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पुलिस के पास सुरक्षा इंतजाम के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा। आदेश में साफ तौर पर लिखा गया, आरसीबी ने पुलिस से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली।

मेरी सच्चाई सीएम को है पता, वही देंगे जवाब

मंत्री संपतिया बोलीं, 1000 करोड़ की घूसखोरी का है आरोप

● मंत्री के खिलाफ जांच कराने वाले अफसर पर होगी कार्रवाई

भोपाल। मध्यप्रदेश की पीएचई मंत्री संपतिया उड़के ने अपने ऊपर लगे 1000 करोड़ के कमीशन लेने के आरोप पर मंगलवार को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल सही हूं, सांच को आंच नहींज जिस तरह से जांच करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी सच्चाई मुख्यमंत्री को पता है, वो जवाब देंगे। इधर, कैबिनेट बैठक में मंत्री के ऊपर लगे आरोप और जांच का मामला उठा। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि अपने ही विभाग की मंत्री के खिलाफ जांच बैठाने वाले पीएचई विभाग के प्रमुख अभियंता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बता दें, पीएचई मंत्री संपतिया उड़के पर 1000 करोड़ रुपए कमीशन लेने के आरोप लगे थे। इस पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग ने उनके खिलाफ जांच बैठा दी थी। प्रमुख अभियंता (ईएनसी) संजय अंधवान ने प्रधानमंत्री से की गई शिकायत और केंद्र की ओर से मांगी गई रिपोर्ट के बाद जांच के आदेश दिए थे। पूर्व विधायक किशोर समरीते ने 30 हजार करोड़ के जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।



डिप्टी सीएम ने कहा- मंत्री पर आधारहीन आरोप

डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र कुमार शुक्ल ने कहा कि ऐसी मंत्री पर आरोप लगाया है जिसका रजनैतिक बैकग्राउंड अच्छा है। लगन के साथ काम कर रही हैं। विधानसभा में बजट प्रस्ताव के दौरान सभी ने उन्हें बधाई दी है। आदिवासी मंत्री को टारगेट करना निंदनीय है और आधारहीन आरोप छवि खराब करने वाला है। जांच के आदेश के बाद सोमवार शाम प्रमुख अभियंता संजय अंधवान ने कहा था कि मंत्री संपतिया के खिलाफ की गई शिकायत निराधार है। उन्होंने मध्यप्रदेश के बालाघाट के कार्यपालन यंत्री की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि शिकायतकर्ता किशोर समरीते की ओर से कोई भी सबूत नहीं दिया गया। केवल सूचना के अधिकार के तहत विभागीय अधिकारी की ओर से भेजे गए पत्र को ही आधार बनाया गया। अंधवान ने कहा कि बालाघाट संभाग के कार्यपालन यंत्री ने किशोर समरीते को यह जानकारी दी थी कि किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है।

मंत्री बोलीं, मैं सही, सांच को आंच नहीं

पीएचई मंत्री संपतिया ने कहा कि जिस तरह से जांच करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के विरुद्ध शिकायत हुई है तो उसकी जांच होती है। किशोर समरीते की ओर से प्रधानमंत्री को की गई शिकायत के बाद मुख्य सचिव कार्यालय को प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्देश मिले थे। मुख्य सचिव ने पीएचई विभाग के प्रमुख सचिव को इसके लिए निर्देशित किया। इसके बाद प्रमुख सचिव ने ईएनसी को इसकी जांच के लिए पत्र आगे बढ़ा दिया। 12 अप्रैल को पीएम को भेजे गए पत्र पर 22 अप्रैल से एमपी में यह प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद 23 अप्रैल, 24 अप्रैल और 25 अप्रैल को इसके निर्देश निचले अफसरों को दिए जाते रहे। प्रमुख अभियंता ने 21 जून को इसकी जांच मुख्य अभियंताओं से कराने संबंधी पत्र जारी किया। प्रमुख अभियंता कार्यालय ने सभी मुख्य अभियंता पीएचई और परियोजना निदेशक मप्र जल निगम को इस मामले में चिट्ठी लिखकर सात दिन में रिपोर्ट देने को कहा। निर्देश में कहा गया कि भारत सरकार ने राज्य के जल जीवन मिशन को दिए 30 हजार करोड़ के खर्च की जांच की जाए। साथ ही पीएचई मंत्री संपतिया उड़के और उनके लिए पैसा जमा करने वाले मंडला के कार्यपालन यंत्री की संपत्तियों की जांच के निर्देश दिए गए थे।

शिकायतकर्ता बोले- कोर्ट में देना होगा जवाब

प्रमुख अभियंता पीएचई अंधवान के बयान के बाद शिकायतकर्ता किशोर समरीते ने कहा था कि सिर्फ बालाघाट में मिशन की कार्यप्रणाली को लेकर जवाब दिया गया है। प्रदेश भर में गड़बड़ी की जांच के लिए खुद ईएनसी ने सभी चीफ इंजीनियरों को चिट्ठी लिखी है। इस मामले में वे जल्दी ही कोर्ट में याचिका लगाने जा रहे हैं और सरकार से इस पर जवाब लेंगे। समरीते ने प्रधानमंत्री के नाम 12 अप्रैल 2025 को शिकायती पत्र भेजा था। जिसमें कहा गया कि एमपी में जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिए गए 30 हजार करोड़ में मंत्री संपतिया ने एक हजार करोड़ रुपए कमीशन लिया है। शिकायत में पूर्व ईएनसी बीके सोनगरिया पर भी आरोप है कि उन्होंने अपने अकाउंटेंट महेंद्र खंके के जरिए कमीशन लिया है। यह राशि 2000 करोड़ है। समरीते ने कहा कि पीआईयू, जल निगम के डायरेक्टर जनरल और इंजीनियरों ने एक-एक हजार करोड़ का कमीशन लिया है। बैतुल के कार्यपालन यंत्री ने 150 करोड़ रुपए बिना काम कराए ही शासन के खाते से निकाल लिए हैं। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा और बालाघाट का भी यही हाल है। मुख्य अभियंता मैकेनिकल द्वारा 2200 टेंडरों पर काम नहीं कराया गया और राशि निकाल ली गई। समरीते ने आरोप लगाया है कि सात हजार काम पूरे होने के फर्जी प्रमाण पत्र भी एमपी से केंद्र सरकार को भेजे गए हैं, जिसकी सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। वह घोटाला देश के बड़े घोटालों में निकलकर आएगा।

मुख्यमंत्री 4 को करेंगे प्रतिभाशाली छात्रों को लैपटॉप वितरित

भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में होगा कार्यक्रम



भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार 4 जुलाई को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में लैपटॉप वितरित करेंगे। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले प्रति विद्यार्थी को 25 हजार रुपये की राशि लैपटॉप क्रय करने के लिये उनके बैंक खाते में अंतरित करेगा। इस वर्ष 94 हजार 234 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिये 235 करोड़ 58 लाख 50 हजार रुपये की राशि दी जा रही है। कार्यक्रम में प्रदेश के 500 से अधिक विद्यार्थी और शिक्षक सहभागिता करेंगे। प्रदेश में पिछले वर्ष 2023-24 में 89 हजार 710 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बैंक

खातों में 224 करोड़ 27 लाख 50 हजार रुपये की राशि अंतरित की गयी थी। प्रदेश में यह योजना वर्ष 2009-10 से संचालित हो रही है। पिछले 15 वर्षों में इस योजना में 4 लाख 32 हजार 16 विद्यार्थियों के बैंक खातों में एक हजार 80 करोड़ 4 लाख रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप लैपटॉप के लिये अंतरित की जा चुकी है।

अब्दुल हमीद का पराक्रम भारतीय सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मां भारती के वीर सपूत अब्दुल हमीद ने युद्ध में पाकिस्तान के तोप नष्ट कर मातृ भूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। भारत के सैन्य इतिहास में उनका पराक्रम और शौर्य एक स्वर्णिम अध्याय है, जिससे युवाओं को संदेव प्रेरणा मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने परमवीर चक्र सम्मानित अमर शहीद अब्दुल हमीद की जयंती पर उन्हें नमन किया।

प्रदेश के शहरी मार्गों पर 582 इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना

चार्जिंग अधोसंरचना के लिए केन्द्र सरकार से मिलेगी 100 प्रतिशत राशि

भोपाल। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिये मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 तैयार की गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा परिवहन कर में छूट और अनुदान दिये जाने की भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश के बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन सेवा के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बस सेवा को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्तमान में इंदौर में शहरी मार्गों पर 80 इलेक्ट्रिक बसों को संचालन किया जा रहा है। फेम योजना के अंतर्गत 40 और अमृत योजना 1.0 में 40 बसें संचालित हो रही हैं। ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत 6 शहरों में 582 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिये प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया था, जिसे केन्द्रीय शहरों



मंत्रालय नई दिल्ली से स्वीकृति मिल गयी है। इंदौर में 150, भोपाल में 100, ग्वालियर में 100, जबलपुर में 100, सागर में 32 एवं उज्जैन में 100 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का प्रस्ताव है। प्रदेश के 6 शहरों में बस संचालन के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा निविदा जारी कर बस संचालकों का चयन किया जा चुका है। पीएम ई-बस सेवा के अंतर्गत बस डिपो अधोसंरचना

निर्माण के लिये भी प्रस्ताव तैयार किया गया है, इसमें 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा और शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदाय की जायेगी। इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग अधोसंरचना निर्माण के लिये केन्द्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत राशि प्रदान की जायेगी। नगरीय निकायों द्वारा बस डिपो एवं चार्जिंग स्टेशन निर्माण के लिये प्राकलन तैयार कर राज्य स्तरीय संचालन समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। अनुमोदन के बाद प्रस्ताव केन्द्रीय शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा गया है। भोपाल एवं जबलपुर शहर द्वारा बस डिपो अधोसंरचना निर्माण के लिये निविदा जारी की जा चुकी है। प्रदेश के शहरों में लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल के संचालन को बढ़ावा देने के लिये भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर शहर में 34 चार्जिंग स्टेशन पर 190 चार्जिंग पाइंट लगाये गये हैं।



आरोपी के खिलाफ नया केस दर्ज करने का आदेश दिया। 23 अप्रैल 2021 की सुबह करीब 4 बजे, फरियादी शाहरूख खान को भोपाल के कालीबाड़ी बरखड़ा इलाके में टिंगू और उसके साथी राजा खान ने रू. 1000 न देने पर चाकू और धारदार हथियार से सिर पर हमला कर दिया था। शाहरूख को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल से सूचना मिलने पर गोविंदपुरा थाना पुलिस हमीदिया अस्पताल पहुंची और शाहरूख की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया। इसके बाद मामला कोर्ट में चला।

पटेल नगर कॉलोनाइजर पर जल्द करें एफआईआर दर्ज

मंत्री कृष्णा गौर बोलीं-मंत्रालय में की मीटिंग, भोपाल की 4 कॉलोनी में हैं समस्याएं

भोपाल। भोपाल के रायसेन रोड स्थित पटेल कॉलोनी के कॉलोनाइजर के विरुद्ध एफआईआर होगी। मंत्री कृष्णा गौर ने नगर निगम के अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं। मंत्री गौर ने मंगलवार को मंत्रालय में बैठक की। वहीं, 4 कॉलोनी के रहवासियों की समस्याओं को लेकर भी बात की। बैठक में मंत्री गौर ने गोविंदपुरा क्षेत्र की सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी संस्था, अग्रोहा गृह निर्माण समिति, कुंजन गृह निर्माण समिति और पटेल नगर कॉलोनी के रहवासियों की समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों से चर्चा भी की। बैठक में बताया गया कि पटेल नगर कॉलोनी में स्कूल, खेल मैदान, पार्क आदि के लिए छोड़े गए भू-खंडों को नगर निगम के लिए सौंपने के स्थान पर कॉलोनाइजर ने इस कॉलोनी के प्राइमरी स्कूल के एक भू-खंड को निजी तौर पर विक्रय कर दिया। नगर निगम के स्वामित्व के इन भू-खंड को विक्रय करने का अधिकार कॉलोनाइजर को नहीं है। कॉलोनाइजर द्वारा किया गया यह कृत्य आपराधिक है। इसे ध्यान में रखते हुए मंत्री गौर ने नगर निगम के अधिकारियों को कॉलोनाइजर के विरुद्ध एफआईआर



दर्ज कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कॉलोनाइजर द्वारा विक्रय किए गए भू-खंड की रजिस्ट्री को शून्य कराने की प्रक्रिया भी शुरू करें। इसके साथ ही कॉलोनाइजर अन्य ओपन एरिया को विक्रय नहीं कर सके, इसकी व्यवस्था भी करें।

यूबी सिटी में समस्याओं की जांच करेंगे हजूर एसडीएम

कोलार रोड पर बोरदा स्थित यूबी सिटी में रहने वाले लोगों ने भी कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से कलेक्टर कोशलेंद्र विक्रम सिंह से शिकायत की है। वे मंगलवार को जनसुनवाई में भी पहुंचे। कलेक्टर से की गई शिकायत में कहा गया है कि यूबी सिटी प्रोजेक्ट में कई लापरवाही की गई है। बिल्डिंग के ब्लॉक-ए, बी और बी1 डुप्लेक्स और बिल्डिंग ग्राउंड प्लेन, सड़क की स्थिति बेहद खराब है। इंटरनल और आउटर वॉल पर प्लास्टर तक नहीं किया गया है। पेंट भी नहीं हुआ है। दोनों गेटों का निर्माण कार्य अधूरा है। इसके अलावा भी कई समस्याएं हैं। इसके बाद कलेक्टर ने हजूर एसडीएम विनोद सोनकिया को जांच सौंपी है। वे जांच कर रिपोर्ट देंगे और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी।



बढ़ावा देने में MPUVNL की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 'पीएम सूर्य घर योजना के तहत आवासीय घरों की छतों पर सोलर लगाने का प्रावधान किया गया है। इसमें पहले दो किलोवॉट के लिए प्रति किलोवाट 30 हजार रुपये और तीसरे किलोवॉट के लिए 18 हजार रुपये सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही है। इस तरह से तीन किलोवाट के रूफटॉप सोलर के लिए कुल 78 हजार रुपये की सब्सिडी उपलब्ध है।' पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर के लाभों को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, 'इस योजना के बहुत सारे लाभ हैं। इस प्रोजेक्ट से गिड पर उपभोक्ता की निर्भरता कम होती है। इससे दिन के समय उपभोक्ता के इस्तेमाल के लिए सस्ती

बिजली उपलब्ध होती है। छतों पर सोलर सिस्टम को लगाने में उपभोक्ताओं की जितनी राशि व्यय होती है, वह पांच से छह वर्ष में रिकवर हो जाएगी। उसके बाद सोलर सिस्टम से बाकी समय में बिजली की बचत के माध्यम से लाभ होगा। इन तीन लाभों के अलावा एक नागरिक होने के नाते उपभोक्ता एक स्वच्छ पर्यावरण, एक क्लीन सस्टेनेबल इको सिस्टम के लिए योगदान कर पाएंगे। एमडी श्री बैस ने बताया कि मध्यप्रदेश अक्षय ऊर्जा नीति 2025 के तहत 2030 तक प्रदेश की कुल बिजली खपत में अक्षय ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी को 50 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसमें राज्य सरकार के हरित ऊर्जा अनुपालन वाले विभागों, मॉडल अक्षय ऊर्जा

शहरों और हरित क्षेत्रों के लिए चरणबद्ध विकास का लक्ष्य रखा गया है, जो 2024 में 20 प्रतिशत, 2027 में 50 प्रतिशत और 2030 में 100 प्रतिशत है। इसके अलावा, 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 50,000 से अधिक नौकरियां पैदा करने का भी लक्ष्य है। एमडी श्री बैस ने बताया कि मध्यप्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए CEEW सक्रियता से काम कर रहा है। प्रदेश के विभागों के सहयोग से, लक्षित आउटरीच पहलों की एक सीरीज के माध्यम से पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना और पीएम-कुसुम जैसी प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन में भी सहयोग कर रहा है। इसमें MPUVNL और नॉलज पार्टनर CEEW मिलकर मध्यप्रदेश के संभागीय कार्यालयों में पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना और पीएम-कुसुम योजनाओं पर जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं। इनका उद्देश्य जिला स्तरीय अधिकारियों और प्रमुख हितधारकों को वर्तमान योजनाओं के बारे में प्रशिक्षित करना और जागरूकता बढ़ाना है। इन कार्यशालाओं में बिजली के अंतिम उपयोग वाले क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को अपनाने के विभिन्न अवसरों को रेखांकित किया जाता है। अब तक पांच संभागों में इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है। जुलाई व अगस्त महीने में भी कुछ अतिरिक्त सत्र आयोजित किये जायेंगे। एमडी श्री बैस ने बताया कि MPUVNL के साथ मिलकर CEEW ने स्थानीय समुदायों तक इन योजनाओं के लाभों, प्रक्रियाओं और अवसरों की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सोलर जागरूकता वैन अभियान भी शुरू किया है। यह अभियान पिछले 110 दिनों से सफलतापूर्वक चल रहा है, जिसमें प्रदेश के कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है और विभिन्न हितधारकों को जोड़ा गया है।

10 साल की सजा सुनते ही कोर्ट से भागा आरोपी

1 हजार न देने पर फरियादी को मारा था चाकू, अब नया केस हुआ दर्ज

भोपाल। भोपाल में हत्या की कोशिश के एक मामले में आरोपी आसिफ खान उर्फ टिंगू उर्फ अरमान को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई। जैसे ही न्यायाधीश नीलू संजीव श्रृंगीच्छ्रि ने फैसला सुनाया, टिंगू कोर्ट से भाग गया। उसके साथी राजा खान को सबूत न होने की वजह से बरी कर दिया गया। टिंगू के फरार होते ही कोर्ट में अफरातफरी मच गई। कोर्ट के कर्मचारियों ने उसे आसपास ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मिला तो एमपी नगर थाना में इसकी सूचना दी गई। न्यायाधीश ने



आरोपी के खिलाफ नया केस दर्ज करने का आदेश दिया। 23 अप्रैल 2021 की सुबह करीब 4 बजे, फरियादी शाहरूख खान को भोपाल के कालीबाड़ी बरखड़ा इलाके में टिंगू और उसके साथी राजा खान ने रू. 1000 न देने पर चाकू और धारदार हथियार से सिर पर हमला कर दिया था। शाहरूख को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल से सूचना मिलने पर गोविंदपुरा थाना पुलिस हमीदिया अस्पताल पहुंची और शाहरूख की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया। इसके बाद मामला कोर्ट में चला।

अब हर पौधे की होगी सेटलाइट से निगरानी

राजधानी भोपाल में वन महोत्सव की शुरुआत

लोक निर्माण विभाग ने लगाए ढाई लाख पौधे

भोपाल। राजधानी के चिनार पार्क में मंगलवार को वन महोत्सव का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने पौधारोपण कर की। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग को 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन विभाग ने ढाई लाख पौधे लगाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि लगाए गए पौधों के रख-रखाव और संरक्षण के लिए सेटलाइट मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जा रही है। इस योजना में अहमदाबाद स्थित भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लिकेशन सहयोग कर रहा है, जिससे हर पौधे की निगरानी डिजिटल रूप से की जा सकेगी। कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि भोजपुर रोड को 4 लेन बनाने की योजना के तहत रास्ते में आने वाले 450 पेड़ों को हटाना था। लेकिन अब इन्हें काटने की बजाय ट्रांसप्लांट (शिफ्ट) किया जाएगा ताकि

पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। विधायक भगवानदास सबनानी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई तक चलेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय हमारे पास पैसे थे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी। प्रकृति हमें बिना किसी लागत के जीवनदायिनी



हवा देती है, इसलिए इसके संरक्षण के प्रति समाज को और जागरूक होना होगा। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बताया कि अब तालाबों और जलस्रोतों का निर्माण बिना योजना के नहीं होगा। हर निर्माण कार्य कलेक्टर की अनुमति और स्थानीय जरूरतों के आधार पर होगा, जिससे भूजल स्तर भी बढ़ेगा और गांवों को स्थायी जलस्रोत मिल सकेगा।

संपादकीय

हिंदी : आदेश वापसी का दांव

महाराष्ट्र में राजनीति का मुद्दा बन चुके स्कूलों में त्रिभाषा फार्मूले के तहत पहली कक्षा से हिंदी अनिवार्य करने के आदेश को राज्य की फंडणवीस सरकार ने विपक्ष के दबाव में वापस जरूर ले लिया है, लेकिन जिस तरह से यह वापस लिया गया है, वह भी नया सियासी दांव हो सकता है। इसका पहला असर तो राज्य में करीब आ रहे दो धुर विरोधी ठाकरे बंधुओं के बीच मन मिलाप अब होगा या नहीं कहना मुश्किल है। दूसरे, मुख्यमंत्री फंडणवीस ने आदेश वापस लेकर विपक्ष के हाथों से वो मुद्दा छीन लिया है, जो राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में महत्वपूर्ण हो सकता है। चूंकि आदेश ही वापस हो गया तो रस्म अदायगी के तौर पर दोनों ठाकरे बंधुओं ने 5 जुलाई को विजय दिवस रैली निकालने का ऐलान किया है, लेकिन इसमें दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अपने झंडे लाने की अनुमति नहीं होगी। यानी कोई भी ऐसा संदेश नहीं दिया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और चचेरे भाई राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सचमुच करीब आती दिखाई दे। शिवसेना और अन्य कुछ संगठनों ने त्रिभाषा फार्मूले को राज्य की जनता पर हिंदी थोपने के रूप में प्रचारित किया। उसने राज्यभर में हिंदी लागू करने के आदेश की प्रतियां जलाने का ऐलान कर दिया। जिसमें राज्य सरकार ने यह आदेश नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में बच्चों को पहली कक्षा से तीन भाषाएँ, जिनमें पहली मातृ भाषा, दूसरी अंग्रेजी और तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ना अनिवार्य किया गया था। महाराष्ट्र में स्कूलों में हिंदी पढ़ाई तो जाती है, लेकिन वह अनिवार्य नहीं है। इस आदेश को राजनीतिक तौर पर भाजपा द्वारा महाराष्ट्र पर मोदी सरकार द्वारा हिंदी थोपने के रूप में प्रचारित किया गया। इसको लेकर कई विपक्षी दल और मराठी साहित्यिक भी एकजुट होने लगे। इस लामबंदी के बाद सत्तारूढ़ महायुति के प्रमुख घटक राकांपा के नेता और राज्य के वित्त मंत्री अजित पवार ने भी तीसरी भाषा के रूप में हिंदी की अनिवार्यता पर सवाल उठा दिए। इससे राज्य में मराठी भाषी बनाम हिंदी भाषी गोलबंदी होने लगी। इसका प्रभाव राज्य में जल्द होने वाले मुंबई महानगरपालिका और स्थानीय निकाय चुनावों में हो सकता था। यही कारण है कि देवेन्द्र फंडणवीस से यह मुद्दा विपक्ष से छीनने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। कैबिनेट बैठक के बाद सहयाद्री गेस्ट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए फंडणवीस ने कहा कि हमने कैबिनेट में तीन-भाषा नीति पर विस्तार से चर्चा की और 16 अप्रैल और 17 जून 2025 को जारी किए गए जीआर को रद्द करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि डॉ नरेंद्र जाधव के नेतृत्व में एक समिति गठित की जाएगी जो यह निर्धारित करेगी कि किस कक्षा से तीन-भाषा नीति लागू की जानी चाहिए, कार्यान्वयन कैसे होना चाहिए और छात्रों को क्या विकल्प दिए जाने चाहिए। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर, राज्य सरकार अंतिम निर्णय लेगी।' इसके पहले उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि स्कूलों में हिंदी पढ़ना वैकल्पिक होगा, न कि अनिवार्य। फंडणवीस ने इसे विपक्ष की 'विनोदी राजनीति' पर निशाना च्यक की और बताया कि शिवसेना (यूबीटी) के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार ने डॉ. रघुनाथ माशेलकर की तीन-भाषा सूत्र रिपोर्ट को बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लिया था। फंडणवीस ने कहा कि यह ठाकरे की सरकार थी, जिसे तत्कालीन कांग्रेस और अविभाजित एनसीपी का समर्थन प्राप्त था, जिसने अंग्रेजी और हिंदी को अनिवार्य बनाने पर सहमति व्यक्त की थी। अभी हालांकि आदेश वापस ले लिया गया है, लेकिन यह मुद्दा डॉ. नरेन्द्र जाधव की रिपोर्ट आने के बाद नए सिर से खुलेगा।

नजरिया

अनुराग बेहार

लेखक अजीम प्रेमजी काउंसेलर के सीईओ एवं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के संस्थापक वाइस चांसलर हैं। अंग्रेजी अखबार दित में प्रकाशित आलेख से अनुदित



केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 22 मई 2025 को एक दिशानिर्देश जारी किया। कुछ अखबारों ने इसकी तीखी आलोचना करते हुए संपादकीय प्रकाशित किए। ये संपादकीय और संबंधित राय के अंश बेहद भ्रामक थे, और मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्हें इन आम तौर पर उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशनों में जगह मिली। यह दिशा निर्देश सीबीएसई द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षण दिए जाने के बारे में था, आइए पहले यह देखते हैं कि यह दिशा निर्देश असल में क्या कह रहा है? यह कहता है कि बच्चे को साक्षर बनाने की पहली भाषा (जिसे आर1 से दर्शाया गया है) वह भाषा जिसमें बच्चा सबसे पहले पढ़ना-लिखना सीख सके- बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। अगर कक्षा में विभिन्न मातृभाषाओं (एक से अधिक भाषाओं) के बच्चे हैं और इस वजह से यह अव्यवहारिक महसूस हो रहा है, तो बच्चों की दूसरी सबसे परिचित भाषा जो कि आम तौर पर स्थानीय रूप से प्रचलित भाषा भी होती है, को उपयोग किया जाना चाहिए। स्पष्ट तौर पर कहें तो बच्चों को उस भाषा में पहले पढ़ना और लिखना सीखना चाहिए जिसे वे पहले से ही जानते हैं। सीबीएसई ने आगे स्पष्ट करते हुए कहा है कि आर1 को ही स्वाभाविक तौर पर दूसरे विषयों के लिए पढ़ाने का माध्यम होना चाहिए, जिसमें आर2 में साक्षरता भी आवश्यक है। इसमें आगे कहा गया है जब एक बच्चा आर1 और आर2 दोनों में साक्षरता हासिल कर लेता है तो दोनों में से किसी भी भाषा को अन्य विषय सिखाने का माध्यम बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि इन जगहों से आने वाली गुमराह करने वाली आलोचना भी इस बात को मानती है कि वैश्विक शोध, अनुभव और सामान्य ज्ञान भी इस बात की पुष्टि करते हैं- बच्चे उस भाषा में कहीं अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ना और लिखना सीखते हैं जिसे वे पहले से जानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके मौजूदा भाषाई और सामाजिक ज्ञान भाषा सीखने में सहायक होते हैं, जिससे उन्हें आसानी से ज्ञात शब्दों को लिखित प्रतीकों से जोड़ने में मदद मिलती है। इसके विपरीत, अपरिचित भाषा में पढ़ना-लिखना सिखाना कठिनाई को और बढ़ा देता है, क्योंकि बच्चों को एक नई भाषा को भी सीखना होता है और उसमें पढ़ने और लिखने की क्षमता भी विकसित करनी होती है। इस मूलभूत सिद्धान्त को स्वीकारते हुए भी यह लिखने वाले लेखक किस तरह से गलत हैं? इस दावे में त्रुटि इस तरह से है कि- इंडियन एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय में 28 मई को लिखा- इस तर्क को पूरे देश के वृहद बहुभाषिक सीबीएसई पारिस्थितिक तंत्र

मातृभाषा में शिक्षा का पूर्व-निर्धारित सोच के चलते विरोध

यह दिशा निर्देश सीबीएसई द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षण दिए जाने के बारे में था, आइए पहले यह देखते हैं कि यह दिशा निर्देश असल में क्या कह रहा है? यह कहता है कि बच्चे को साक्षर बनाने की पहली भाषा (जिसे आर1 से दर्शाया गया है) वह भाषा जिसमें बच्चा सबसे पहले पढ़ना-लिखना सीख सके- बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। अगर कक्षा में विभिन्न मातृभाषाओं (एक से अधिक भाषाओं) के बच्चे हैं और इस वजह से यह अव्यवहारिक महसूस हो रहा है, तो बच्चों की दूसरी सबसे परिचित भाषा जो कि आम तौर पर स्थानीय रूप से प्रचलित भाषा भी होती है, को उपयोग किया जाना चाहिए। स्पष्ट तौर पर कहें तो बच्चों को उस भाषा में पहले पढ़ना और लिखना सीखना चाहिए जिसे वे पहले से ही जानते हैं।

में एक समान लागू करने में बहुत सी जटिलताएँ सामने आती हैं। ऐसे शहर और कस्बे जहाँ कक्षाओं में विभिन्न भाषा-भाषी समुदायों के बच्चे आते हैं.....यहाँ विविध भाषाओं वाली कक्षा में काम करना कैसे संभव होगा ? तब किस भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी? इस तरह के बयानों से यह साबित होता है कि आलोचकों ने या तो सीबीएसई के दिशानिर्देशों को ठीक से पढ़ा नहीं या फिर समझने में विफल रहे हैं- या फिर यह भी हो सकता है कि यह इंग्लिश के



विस्थापित होने के डर से उपजा सामान्य विद्रोह है, जो कि इससे जुड़े ज्यादातर बयानों से जाहिर होता है सीबीएसई के दिशानिर्देशों ने पहले ही बहुभाषिक माहौल की जटिलताओं को सीधे तौर पर संबोधित करते हुए बात रखी है। अगर इस तर्क के साथ जाएँ तो स्थानीय रूप से उपयुक्त भाषा को आर1 के रूप में चुनना चाहिए- जो कि बहुभाषिक जटिलता का समाधान प्रस्तुत करता है न कि दिक्कत बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ इस तरह के दावों में आलोचकों के द्वारा जो तर्क दिये जा रहे हैं वह दुराग्रही महसूस होते हैं क्योंकि- वे बहुभाषिक माहौल में अंग्रेजी को एकसमान रूप से लागू किए जाने की वकालत करते हैं- जो कि अप्रोच के तौर पर गहरे रूप में दोषपूर्ण और निष्क्रिय है, क्योंकि भारत के किसी भी बहुभाषिक माहौल में अधिकांश बच्चों के लिए अंग्रेजी सबसे

अपरिचित भाषाओं में से एक है। इस अखबार के पढ़ने वालों के लिए एक चेतावनी है- अपने बच्चों या नाती-पोतों की छवि को देखकर मंत्रमुग्ध मत होइए- जो कि इस देश का मात्र 2 प्रतिशत भर होंगे, बाकी के 98 प्रतिशत के लिए तो अंग्रेजी अभी भी एलियन है खास तौर से उनकी शुरुआती बाल्यावस्था में । इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं- मान लीजिए मैंगलोर की कक्षा 1 का दृश्य है, यहाँ बच्चों की मातृभाषाओं में कन्नड़, मलयालम, उर्दू, तुलु और

कोंकणी शामिल हो सकती है। चूंकि यह बच्चे मैंगलोर में रहते हैं इसलिए उनकी मातृभाषा के अलावा उनका परिचय कन्नड़ से है, वे अंग्रेजी जानते होंगे इसकी संभावना कम है। इसलिए आर1 के तौर पर कन्नड़ ही ठीक रहेगी, हो सकता है कि उनमें से कुछ की यह मातृभाषा हो और कुछ इससे परिचित भर होंगे। पर इसके विपरीत अंग्रेजी सबके लिए एक अपरिचित भाषा ही होगी। यह परिदृश्य पूरे भारत में देखा जा सकता है। बड़े मेट्रो शहरों में भी जिसमें प्रवासी लोग बाहर से आते हैं, वहाँ भी बच्चों की स्थानीय भाषा को जानने की संभावना अंग्रेजी जानने से अधिक है। इसलिए सीबीएसई का दिशानिर्देश देश की बहुभाषिक वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक तौर पर साक्षरता के लिए सही दृष्टिकोण है। सीबीएसई के इस कदम ने व्यवस्था में सबसे गहरे

तौर पर जमे मुद्दे को लक्षित किया है- साक्षरता को किस तरह से प्राप्त किया जाए, जो सभी तरह से सीखने और उसके बाद की शिक्षा का भी आधार है। हालांकि केवल एक परिचित भाषा का उपयोग अपने आप में साक्षरता की समस्या के संपादकों में पर्याप्त नहीं है लेकिन यह केंद्रीय और आवश्यक है। शिक्षा में सुधार करने के लिए और इसे ज्यादा न्यायसंगत और समावेशी बनाने के लिए हमें भारत में साक्षरता दर के संकट और इसे संबोधित करने की तात्कालिकता को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यह सोच त्वरित व अयोग्य है साथ ही तकनीकी शैक्षिक मुद्दों पर नियंत्रण की कमी दिखाती है कि हमारे अभिजात्य वर्ग की सोच पर अंग्रेजी कितनी मजबूती से हावी है और यह इन अखबारों के संपादकीय में साफ झलकता है। क्या कोई भी अखबार अस्पताल में हृदय रोग संबंधी प्रोटोकॉल के बारे में इस तरह के भ्रामक विचार छापने की हिम्मत करेगा? नहीं, क्योंकि यह बेहद तकनीकी मामला है। फिर भी शिक्षा में सबसे तकनीकी मामलों पर भी बिना सोचे समझे इस तरह के विचार दिए जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अंग्रेजी सामाजिक और आर्थिक रूप से आकांक्षापूर्ण बनी हुई है। इसलिए, बहुत से लोग चाहते हैं कि हर भारतीय बच्चा अंग्रेजी सीखे। आलोचक यह पहचानने में विफल रहे कि सीबीएसई का यह दृष्टिकोण अंग्रेजी पढ़ाने और साक्षरता दोनों के लिए कहीं अधिक प्रभावी होगा। किसी परिचित भाषा में साक्षरता प्राप्त करना यानी पढ़ना-लिखना सीखना कहीं ज्यादा प्रभावी होता है, अंग्रेजी बाद में भी सीखी जा सकती है। यह जबरदस्ती अंग्रेजी जैसी अपरिचित भाषा में साक्षरता सीखने से कहीं अलग है, जो अंग्रेजी और पढ़ना-लिखना सीखना दोनों को दुष्कर बना देता है। जिस तरीके की वकालत आलोचकों द्वारा की जा रही है वह न केवल साक्षरता बल्कि अंग्रेजी सीखने को भी और मुश्किल कार्य बना देगा। भारत के हजारों तथाकथित अंग्रेजी-माध्यम स्कूलों में से किसी में भी जाएँ, और आप देखेंगे कि बच्चे पढ़ने-लिखने और अंग्रेजी सीखने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। हमें सीबीएसई के शैक्षणिक रूप से सही और साहसी दृष्टिकोण की सराहना करनी चाहिए, न कि इसकी निंदा करनी चाहिए।

राजनीति

राजेन्द्र जोशी

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।



कांग्रेस पार्टी के द्वारा मप्र में अपने संगठन को मजबूत करने और नये सिर से पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक,संगठनतात्मक बदलाव को लेकर पर्यवेक्षको के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया कर्वाई जा रही है। और कहा जा रहा है कि इससे कांग्रेस संगठन मजबूत होगा,प्रयास और सोच अच्छे है,लेकिन हकीदती में कांग्रेस पार्टी आम आदमी और जमीनी नरुद को से कोसों दूर है। सन् 2018 में 15 सालो के बाद मप्र की सत्ता में वापस आई कांग्रेस पार्टी आपसी खीचतान के चलते,पंद्रह महीने बमुश्किल अपनी सरकार चला पाई,आपसी अंतर्कलह के चलते सत्ता से बाहर तो हो ही गई कई कांग्रेसी पार्टी छोड़कर चले गये तो कई पार्टी विधायको ने विपक्ष को सहयोग देकर उन्हें सत्तारूढ कर दिया,इन 15 महीनों के शासन में कांगेस पार्टी न तो संगठन मजबूत कर पाई नही कार्यकर्ताओं को एक कर सकी आपसी आरोप प्रत्यारोप के चलते 2023 में मप्र में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर ऐसा जताया कि वही सरकार बना रही है, लेकिन हुआ वह सबके सामने है। और इस चुनाव में जो बचे हुये असंतुष्ट कांग्रेसी थे,उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो कई कांग्रेसजन दबाव के चलते चुनाव से दूर हो गए। वर्तमान समय मे मप्र में पंचायत स्तर से प्रदेश स्तर तक गिनती के नेता और जनप्रतिनिधी बचे है जो आम आदमी,समाज,गांव,नगर की विभिन्न समस्याओ के लिये आगे आते होंगे,न ही आमजनो से मिलने के लिये पदाधिकरी उत्स्थित रहते,प्रदेश के कई जिलो में तो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय चुनाव के अवसरो को छोडकर सुने नजर आते है। कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे नेता भी नहीं है जो

आम आदमी और मुद्दों से कोसों दूर कांग्रेस

सरकार की योजनाओं के सही तरीके से क्रियान्वयन न होने पर मुखर होकर मोर्चा खोल सके,साथ ही साथ पंचायत से लेकर जिले तक इनका परीक्षण कर सके योजना क्या है और इसका लाभ वास्तविक हितग्राहियों को मिल पा रहा है या नहीं। और ये योजनाएं कोई नई नहीं है आम समस्या बिजली, पानी, सड़क शिक्षा और स्वास्थ्य राशन रोजगार से जुडी हुई है साथ ही आम आदमी के काम पटवारी से लेकर तहसील कार्यालय से ज्यादा के नही होते है, लेकिन उन कायों में उसकी मदद के लिये नियमित



सहयोग करने वाले नहीं है। केन्द्र व राज्य सरकार कई ऐसी योजनाए है, जिसमें भ्रष्टाचार की बात तो कांग्रेसजन करता है लेकिन उसे पूरी तरह से उजागर नहीं कर पाता है,नहीं उसकी तह में पहुंच पाता है,आज जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हर घर नल योजना की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि सम्बन्धित सरकारी एजेंसियों को दिसम्बर 2024 तक पूर्ण करना था लेकिन यह आज भी कई गांवों में पूर्ण नही हो पाई है कई ग्रामों के निवासी आज भी पानी की समस्या से जुझ रहे है लेकिन कांग्रेसजन उस पर कुछ करना ही नहीं चाहते है। बीते गमी के मौसम में भाजपा व कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र में पानी की

समस्या को देखते हुये पानी के टैंकों का वितरण सम्बन्धित पंचायतों को किया है,जो बताता है कि हर घर पानी नहीं पहुंचा।

केन्द्र सरकार की एक और महत्त्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना है,जिसे गांव,गांव जाकर देने के साथ यह भी पता करना चाहिये जिन्हे सालों बाद भी लाभ नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, उदाहरण के लिये बड़वानी जिले की जनपद बड़वानी के ग्राम आमलियापानी के जुरदार सिंह को आज तक आवास नहीं मिला,वे बताते है पंचायत सचिव कहता है तुम्हें नहीं मिलेगा क्यों कि तुम इसका लाभ ले चुके हो,जुरदार का कहना है तो मेरी कुटीर कहा बनी है पंचायत बताये। ऐसी और कितनी समस्या हो सकती है। आज बेहतर रोजगार के लिये आदिवासी जिलों से प्रतिदिन सैकड़ोजन अन्य प्रदेशों में रोजगार हेतु पलायन करते है उसके बारे में गम्भीरता से कोई विचार नही करता है गाढे बगाहे किसी नेता का बयान आ जाता है लेकिन कोई यह नही पूछता है कि हमारे प्रदेश में रोजगार क्यों नहीं है।

दूसरी और प्रदेश सरकार स्वास्थ और शिक्षा निजीकरण कि और बढ़ रही है

बड़वानी जिला चिकित्सालय के एक प्रयोगशाला कर्मचारी ने बताया कि लेबोर्टरी से लगाकर सोनोग्राफी तक निजी हाथों में जा रही है सरकार तकनीकी कर्मचारियों कर भरती नहीं कर रही है आने वाले समय में सब कुछ निजी रहेगा,ऐसा ही कुछ शिक्षा के क्षेत्र में चल रहा है और उसकी शुरुआत तीन साल पहले प्रदेश की राजधानी भोपाल के नन्ददीक्ष सिंहेर जिला मुख्यालय में स्थित शा.कन्या शिक्षा परिसर से हो चुकी है।

जन सामान्य से जुड़े ऐसे मुद्दे है जिसपर कांग्रेस के नेता मौन साधे है जबकि इनपर स्थानीय स्तर से प्रदेश स्तर तक मुखला आवश्यक है नहीं तो आने वाले समय में निजीकरण को कोई नही रोक पायेगा।

बांग्लादेश में कट्टरवाद

डॉ. भूपेन्द्र कुमार सुह्रे



बांग्लादेश आज जिस राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संकट से गुजर रहा है, वह केवल आंतरिक सत्ता-संघर्ष या चुनावी समीकरणों तक सीमित नहीं है। यह संकट कहीं गहरा, बहुआयामी और चिंताजनक है। एक ओर जहां बांग्लादेश की जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली और प्रशासनिक स्थिरता की उम्मीद कर रही है, वहीं दूसरी ओर इस्लामी कट्टरवाद की लहर फिर से सिर उठा रही है। यह लहर केवल धार्मिक उन्माद नहीं, बल्कि एक संगठित वैचारिक आंदोलन है जिसका लक्ष्य देश की धर्मीरप्रेक्ष पहचान, अल्पसंख्यक अधिकारों और सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता को खत्म करना है। राजनीतिक वैक्यूम में कट्टरपंथी ताकतों का उदय- मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में चल रही अंतरिम सरकार की कमजोर नीतियों और प्रशासनिक असफलताओं ने कट्टरपंथी संगठनों को खुलकर सांस लेने का मौका दे दिया है। हिफाजत-ए-इस्लाम, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश (आईएबी), खिलाफत मजलिस (चरु), बांग्लादेश खिलाफत मजलिस (बोकेरम), जमीयत उलमा-ए-इस्लाम और नेजाम-ए-इस्लाम (एनआई) जैसे संगठन अब सड़कों पर आक्रामक रैलियों और सांप्रदायिक नारों के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। 3 मई, 2025 को ढाका में हिफाजत-ए-इस्लाम की विशाल रैली इसका ताजा उदाहरण है। फरवरी 2026 में संभावित आम चुनावों के मद्देनज़र इन इस्लामी दलों ने एक संपर्क समिति भी बना ली है। उनकी रणनीति स्पष्ट है- धार्मिक भावनाओं को भड़का कर और सामाजिक ध्ववीकरण कर वोट बैंक तैयार करना।

लोकतंत्र और सांस्कृतिक अस्मिता पर संकट

चुनावी समीकरणों में कट्टरवाद का समीकरण- इतिहास गवाह है कि इन दलों की चुनावी उपलब्धियां सीमित रही हैं। 1991 से लेकर 2008 तक के चुनावी आँकड़े बताते हैं कि जमात-ए-इस्लामी समेत अधिकांश इस्लामी दलों की सीटें नापथ्य रहीं। फिर भी यह तथ्य नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जब भी इन दलों ने गठबंधन का राजनीति की, उन्होंने सत्तासीन होकर लोकतंत्र विरोधी और असहिष्णु नीतियों को बढ़ावा दिया। 2001 से 2006 तक बीएनपी-जमात गठबंधन सरकार के दौरान अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, पत्रकारों का उत्पीड़न और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर हमले इसके ज्वलंत उदाहरण रहे हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक स्वतंत्रता पर सुनियोजित हमला- कट्टरपंथी संगठनों का असली एजेंडा केवल सत्ता तक सीमित नहीं है। वे बांग्लादेश के सामाजिक ताने-बाने, सांस्कृतिक गतिविधियों और महिलाओं की स्वतंत्रता पर भी सीधा हमला कर रहे हैं। संगीत, थिएटर, महिला फुटबॉल मैच, पर्वग उत्सव जैसे तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों को 'इस्लाम विरोधी' बताकर रोक़ा जा रहा है। महिला सुधार आयोग की सिफारिशों पर जिस तरह से इन संगठनों ने उग्र विरोध और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है, वह उनकी स्त्री विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। विवाह के भीतर बलात्कार को अपराध की श्रेणी में लाने, यौनकर्मियों के श्रम अधिकार सुनिश्चित करने जैसे सुधारात्मक प्रस्तावों पर उनका आक्रोश लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी नफरत का परिचायक है। अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले और प्रशासनिक मूकदर्शिता- हिंदू, बौद्ध और ईसाई अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं।

मंदिरों, घरों और व्यवसायों को ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन अंतरिम सरकार की ओर से कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो रही। जो घटनाएँ हो रही हैं, उनमें प्रशासन की भूमिका अधिकतर 'मूकदर्शक' जैसी रही है। यह स्थिति बांग्लादेश के लिए गंभीर सामाजिक विघटन का कारण बन सकती है। अंतरिम सरकार का ढुलमुल रवैया- सरकार की असफलता केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने में ही नहीं, बल्कि वैचारिक स्पष्टता के अभाव में भी दिख रही है। जब धार्मिक मामलों का सलाहकार स्वयं हिफाजत-ए-इस्लाम और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश का सक्रिय सदस्य हो, तब सरकार से कट्टरपंथियों पर कठोर कार्रवाई की उम्मीद करना निरर्थक है। सरकारी मंचों से 'इस्लामी संस्कृति और मूल्यों को बढ़ावा देने' की घोषणाएँ इस चिंता को और प्रगाढ़ कर देती हैं कि क्या प्रशासन जानबूझकर इस्लामी कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहा है? बांग्लादेश भावि: संघर्ष या आत्मसमर्पण?- आज बांग्लादेश एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। या तो देश का नागरिक समाज, मीडिया, प्रबुद्ध वर्ग और अंतरराष्ट्रीय समुदाय एकजुट होकर इस कट्टरपंथी खरबे का सामना करेगे, या फिर बांग्लादेश एक बार फिर लोकतंत्र, मानवाधिकार और सांस्कृतिक विविधता से पीछे हटकर धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता की दलदल में फंस जाएगा। जरूरत इस बात की है कि अंतरिम सरकार कठोर इच्छाशक्ति दिखाए, सांप्रदायिक तत्वों पर शिकंजा कसे और अल्पसंख्यकों व महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। बांग्लादेश के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए यह संघर्ष आज निर्णायक बन चुका है।

स्वामी, सुबह सवेंरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धिविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जौन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक

उमेश त्रिवेदी

कार्यकारी प्रधान संपादक

अजय बोक्लि

संपादक (मध्यप्रदेश)

विनोद तिवारी

वरिष्ठ संपादक

पंकज शुक्ला

प्रबंध संपादक

अरुण पटेल

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)

RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,

Ph. No. 0755-2422692, 4059111

Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

लंग्य

संजय तैलग

लेखक व्यंग्यकार हैं।



सुबह की सैर अच्छी सेहत के लिए प्राणवायु है। और हो भी क्यों नहीं, सुबह खुशनुमा मौसम और ताजा हवा का साथ मिलने से शरीर दिनभर तरोंताजा जो बना रहता है। सारे दिन ऊर्जा उच्च स्तर पर बनी रहती है। हर काम में मन लगाता है, काम में गति से संपन्न होते है। भोजन को पचाने में अमशय को अधिक मशकत नहीं करनी पड़ती। गोड़े (घुटने) भी बराबर काम करते हैं। सुबह की सैर के इन फायदों में अब एक फायदा और जुड़ गया है। इसका नाम है पूजा के लिए फूलों की जुगाड़। चूंकि, यह मामला सीधे जेब से जुड़ा है, इसलिए इसे विशेष फायदों में गिना जा सकता है। सुबह की सैर पर नियमित जाने वालों ने उनकी तरह ताजा हवा खाने निकले अनेक लोगों के हाथों में प्लास्टिक (पॉलीथिन) की थैली देखी होगी। सुबह-सुबह सेहत के लिए हार्मफुल इस उत्पाद को देख हैरत में पड़ जाने वाले 'सुबह के सैलानी' शायद इस थैली की महिमा नहीं जानते। वैसे वे जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि सेहत के

लिए सही न मानी जाने वाली एक अदद थैली के बारे में विचार कर वे सुबह की सैर का मजा किरकिया करना नहीं चाहते। बहरहाल, वे अपनी ही धुन में रमे कदम बढ़ाए जा-खुशियों के गीत जाए जा के साथ अपने काम (सैर) पर ही फोकस रखते हैं। दरअसल, हाथ में प्लास्टिक की थैली लिए सुबह की सैर पर निकले ये कतिपय 'सुबह के ये सैरिये' 'एक पंथ दो काज' के मुखवरे को पूरी तरह सार्थक कर रहे हैं। 'सुबह की सैर की सैर' और 'घर में विराजित देवों के लिए फूलों की जुगाड़' अलग से और वह

फूलों की चोरी से फूले न समाते फूल चोर

भी बिल्कुल पड़ते। बाजार से फूल लाने पर पांच-दस रुपए गांठ से ढीले करने मुड़ते, लेकिन सुबह-सुबह फूलों से भरे उनमें प्लास्टिक बैग के लिए उन्हें एक ढेला नहीं देना। और तो और दोहरे लाभ से फूले न समाते उन सुबह के सैरियों की आवाज में अलग खनक भी सुनी जा सकती है 'आज तो थैली पूरी भर गई। कम से कम बीस रुपयों के तो होंगे। आज यही बीस रुपए कमाए।' जाहिर है जिन्होंने घर के ग्रीन बेड्ट में फूलों के पौधे लगाकर उन्हें जलन से सींचा, खाद-पानी देकर बड़ा किया, उन्हें देर से जागने की कीमत अपने गंजे हो चुके पौधों के रूप में चुकानी ही है। फूल चोरों को कोस कर सुबह-सुबह अपना मूड बिगाड़ने के अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं है। क्योंकि, गमलों-क्यारियों में लगे सुंदर फूलों को न देख मन मसोसना या उसके लिए जिम्मेदारों को कोसने से डाल से टूटे फूल तो वापस आने से रहे! मन को हल्का करने के लिए ये पौधों की सूनी डालों को देख बुझे मन और लाल आंखों से चार सिक्के सुनकर मन को हल्का करने की नाकाम कोशिश करते हैं। उनके मुखारविंद से निकले सिक्के हवा में तैर कर शुद्ध हवा को थोड़ा प्रदूषित कर, थोड़ा देर में शांत

हो जाते हैं। अब बात उन लोगों की, जो घरों में विराजित भगवान की पूजा के लिए सुबह-सुबह फूलों की चोरी जैसा आराध कर आए हैं। चंद रुपए बचाने के लिए किसी का मन दुखाने का उन्हें जरा भी मलाल नहीं, प्रभु पर चोरी के फूल चढ़ाने का भी उन्हें कोई भय नहीं। ऊपर से कुछ रुपए बचाने की खुशी उनके चेहरों पर साफ झलकती देखी जा सकती है। दरअसल, डालियों से फूलों को अलग करने की उनकी सोच कुछ अलग है, 'पौधे और फूल तो कृति की इंसानों को देन हैं, यदि उन्हें अपनी थैली में रख लिया, तो क्या बुरा किया।' इस पॉजिटिव सोच के साथ अगले दिन दूने उसाह से फूलों की चोरी का एलान भी उनके दिमाग में कुलांच भरने लगता है। उधर, चोरी के फूलों से सजे अंतर्धामी प्रभु नादान भक्त की सोच पर हैरान हैं। सोच रहा होते हैं, कैसा भक्त है। मेरी सब कुछ जानने की शक्ति से वाकफ होने का भी इसे डर नहीं। चोरी के फूलों से मेरी अर्चना करने की इसे क्या सजा दी सकती है! इसी पसपेश में प्रभु आगे सोचना बंद कर, बस कृपा बरसाने वाला हाथ पीछे खींच फिर प्रसन्न मुद्रा में आ जाते हैं।

दृष्टिकोण

भारत डोगरा

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।



महात्मा गांधी की विरासत स्वतंत्र भारत में अनेक अहिंसक आंदोलनों के रूप में फलती-फूलती रही है। इससे कई सार्थक परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसके बावजूद इस समय देश में निरंतरता से सार्थक बदलाव को आगे बढ़ाने वाले किसी बड़े व व्यापक प्रयास का अभाव है। वास्तव में पूरे विश्व स्तर पर ही बढ़ते अनिश्चय व गंभीर होती समस्याओं के बीच वैचारिक संकट है व परिपक्व माने जाने वाले लोकतंत्रों में भी मनमानी के निर्णय लिए जा रहे हैं।

इस स्थिति में यदि भारत में कोई ऐसा अहिंसक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन उभरता है जिसकी सोच देश के साथ पूरे विश्व की भलाई की सोच हो, जो इसके लिए निरंतरता से व्यापक स्तर पर लोगों को जोड़ सकता है व जो बुनियादी बदलाव की राह पर चलते हुए साथ में बहुत से लोगों के दुख-दर्द को कम करते हुए आगे बढ़ते है तो यह एक ऐसी उपलब्धि होगी जिसका लाभ देश के साथ विश्व स्तर पर भी मिल सकेगा।

इसके पहले कदम के रूप में जरूरी है कि दुनिया और देश के स्तर पर जो आगे की उचित राह होनी चाहिए उसके बारे में एक दस्तावेज तैयार किया जाए। इतना तो मानकर चला जा सकता है कि इसके मुख्य सिद्धान्त हैं - न्याय व समता, अमन-शांति व अहिंसा, पर्यावरण व जैव-विविधता की रक्षा, लोकतंत्र व पारदर्शिता, विकेन्द्रीकरण व बढ़ता आपसी सहयोग तथा बेहतर सामाजिक संबंध।

इन सिद्धान्तों के आधार पर देश और दुनिया की भावी राह तय करने के साथ इन्हें अधिक से अधिक लोगों तक ले जाना जरूरी है। विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए इन सिद्धान्तों का कैसे उपयोग किया जाए? अपना, आसपास का जीवन, देश व दुनिया की स्थिति बेहतर करने के लिए इन सिद्धान्तों के आधार पर क्या राह निकाली जाए? यह सवाल बहुत जरूरी है व सही शिक्षा की प्राप्ति और प्रसार तो ऐसे सवालों के उत्तर खोजने में ही निहित है।

स्कूल का प्रथम दिन

श्याम कुमार कोलारे

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।



ग्रीष्मकालीन अवकाश के पश्चात जैसे ही स्कूल पुनः खुलते हैं, एक नई उमंग, उत्साह और उत्सास का वातावरण निर्मित होता है। विशेष रूप से यह दृश्य जून के मध्य में अधिक देखने को मिलता है, जब गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद विद्यालयों में बच्चों की चहचहाहट और किलकारियाँ एक बार फिर लौट आती हैं। दो महीने तक शांत पड़ी स्कूल की इमारतें, प्रांगण, कक्षा-कक्ष और पुस्तकालय अब बच्चों की भाग-दौड़, शोरगुल और हँसी-मजाक से फिर जीवंत हो उठते हैं। यह दृश्य न केवल शिक्षकों के लिए सुखद होता है बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक संदेश लाता है - शिक्षा का क्रम पुनः आरंभ हो चुका है। स्कूल खुलने के समय सबसे अधिक उत्साह उन छोटे बच्चों में होता है जो पहली बार स्कूल का अनुभव लेने जा रहे होते हैं। ये बच्चे घर के लाड़-प्यार और दुलार से निकलकर एक ऐसे नए संसार में प्रवेश करते हैं जहाँ उन्हें शिक्षा की पहली दीक्षा मिलती है। माता-पिता की गोद छोड़कर शिक्षक की उँगलियों को पकड़कर चलने की शुरुआत उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा का पहला चरण होती है। इन बच्चों के लिए स्कूल एक नई दुनिया होती है - नई जगह, नए लोग, नए दोस्त, नए नियम और नई दिनचर्या। यह परिवर्तन उन्हें उत्साहित तो करता ही है, साथ ही थोड़ी घबराहट और डर भी उनके मन में होता है। परंतु धीरे-धीरे जैसे ही वे कक्षा और शिक्षक से परिचित

लोगों को जोड़ने के लिए अहिंसक आंदोलन

इस स्थिति में यदि भारत में कोई ऐसा अहिंसक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन उभरता है जिसकी सोच देश के साथ पूरे विश्व की भलाई की सोच हो, जो इसके लिए निरंतरता से व्यापक स्तर पर लोगों को जोड़ सकता है व जो बुनियादी बदलाव की राह पर चलते हुए साथ में बहुत से लोगों के दुख-दर्द को कम करते हुए आगे बढ़ता है तो यह एक ऐसी उपलब्धि होगी जिसका लाभ देश के साथ विश्व स्तर पर भी मिल सकेगा। इसके पहले कदम के रूप में जरूरी है कि दुनिया और देश के स्तर पर जो आगे की उचित राह होनी चाहिए उसके बारे में एक दस्तावेज तैयार किया जाए। इतना तो मानकर चला जा सकता है कि इसके मुख्य सिद्धान्त हैं - न्याय व समता, अमन-शांति व अहिंसा, पर्यावरण व जैव-विविधता की रक्षा, लोकतंत्र व पारदर्शिता, विकेन्द्रीकरण व बढ़ता आपसी सहयोग तथा बेहतर सामाजिक संबंध।

एक ओर ऐसे आंदोलन को इन सिद्धान्तों के आधार पर देश और दुनिया की आज से कहीं बेहतर व्यवस्था की पहचान बनानी होगी। यह कुछ इस तरह किया जाएगा कि एक ओर लोगों का दुख-दर्द बहुत कम किया जा सके तथा दूसरी ओर धरती की जो जीवन क्षमताएं संकटग्रस्त हो गई हैं, उन्हें समय रहते बचा लिया जाए तथा इस तरह भावी पीढ़ियों का जीवन भी सुरक्षित किया जाए। इस विमर्श व नियोजन में जरूरी है कि जो समाधान सामने आए वे एक-दूसरे से मेल रखने वाले हों तथा सभी मनुष्यों के साथ अन्य जीवन-रूपों की भलाई पर भी समुचित ध्यान दिया जाए।

दूसरी ओर, इस आंदोलन को चाहिए कि वह ऐसी राह अपनाए जिस पर चलते हुए बहुत से लोग अपने दुख-दर्द को कम कर सकें। अन्याय व विषमता कम होने से तो दुख-दर्द कम होते ही हैं, साथ में तरह-तरह के नशे, दैनिक जीवन में हिंसा, टूटते बिखरते सामाजिक संबंधों जैसी समस्याओं के



कम होने से भी दुख-दर्द कम होता है। अतः आंदोलन की बुनियादी बदलाव की ओर बढ़ते हुए ऐसे सतत् रचनात्मक प्रयास करने चाहिए जिससे कि सभी तरह के दुख-दर्द कम होते जाएं व इस आधार पर अनेक लोग आंदोलन से जुड़ते रहें।

अन्याय व विषमता के विरुद्ध संघर्ष करने के साथ-साथ ऐसे बहुत से रचनात्मक कार्य जरूरी हैं जिनसे टिकाऊ रोजगार बढ़ते हैं, किसानों व दस्तकारों की आजीविका मजबूत होती है, गांवों की आत्म-निर्भरता बढ़ती है और आपसी सहयोग से समस्याएं कम होती हैं। इस तरह के रचनात्मक प्रयासों को निरंतरता से बढ़ाना चाहिए। समता व पर्यावरण रक्षा आधारित सामुदायिक जीवन के अनेक प्रयोग करने चाहिए जो वैकल्पिक जीवन की राह प्रस्तुत करें।

ऐसे आंदोलन का एक चुनावी राजनीतिक पक्ष भी होना चाहिए। इसके अन्तर्गत पहले स्थानीय और फिर राज्य व राष्ट्रीय स्तर के चुनावों में राजनीतिक दल बनाकर उम्मीदवार खड़े किए जा सकते हैं या स्वतंत्र उम्मीदवारों को समर्थन दिया जा सकता है। आंदोलन अपनी राह पर चलता रहेगा व चुनावी राजनीति के लिए कोई समझौते नहीं किए जाएंगे। अपनी राह पर चलते हुए जितनी चुनावी सफलता मिले या न मिले, उसे स्वीकार करते

हुए आंदोलन अपनी राह पर बना रहेगा।

इस आंदोलन को अहिंसक होने के साथ-साथ लोकतांत्रिक तौर-तरीके व पारदर्शिता अपनाना चाहिए। उसकी सभी गतिविधियां गुप्त न होकर सार्वजनिक व पारदर्शी हों। धन प्राप्त करने के स्रोत, हिसाब-किताब सभी पारदर्शी होने चाहिए। यदि कोई सदस्य आंदोलन से एक होते हुए कुछ मुद्दों पर अलग राय रखता है, तो उस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। ऐसे आंदोलन की अपनी राह और अपने विकल्पों को आगे ले जाने पर अधिक ध्यान देना चाहिए व दूसरों की या विरोधियों की कटु आलोचना पर अपनी शक्ति नहीं लगानी चाहिए। जहां आलोचना जरूरी हो वहां वह मर्यादित व शालीन रहे।

आंदोलन को चाहिए कि स्वयं पूरी तरह अहिंसक होते हुए अपने संघर्षशील साधियों की रक्षा के पूर्ण प्रयास करें तथा जहां किसी का उत्पीड़न हो, उस साथी को समुचित सहायता पहुंचाने की व्यवस्था करें। वैसे भी आंदोलन के सभी सदस्यों में परस्पर सहायता व सहयोग की स्थिति बढ़ती रहना चाहिए। विभिन्न स्तरों पर गांवों व बस्तियों में, शहरों व महानगरों में आंदोलन को अपने सदस्यों व समर्थकों को ऐसी जगह देनी चाहिए जहां वे गीत-संगीत के बीच प्रेरणादायक स्थितियों में अपने विभिन्न साधियों के साथ बेहतर जीवन व बेहतर दुनिया के नियोजन व सपनों को जी सकें व प्रेरणादायक स्थितियों में अपना योगदान दे सकें। (संप्रेस)

नई दुनिया की ओर बच्चों का पहला कदम

स्कूल खुलने के समय सबसे अधिक उत्साह उन छोटे बच्चों में होता है जो पहली बार स्कूल का अनुभव लेने जा रहे होते हैं। ये बच्चे घर के लाड़-प्यार और दुलार से निकलकर एक ऐसे नए संसार में प्रवेश करते हैं जहाँ उन्हें शिक्षा की पहली दीक्षा मिलती है। माता-पिता की गोद छोड़कर शिक्षक की उँगलियों को पकड़कर चलने की शुरुआत उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा का पहला चरण होती है। इन बच्चों के लिए स्कूल एक नई दुनिया होती है - नई जगह, नए लोग, नए दोस्त, नए नियम और नई दिनचर्या। यह परिवर्तन उन्हें उत्साहित तो करता ही है, साथ ही थोड़ी घबराहट और डर भी उनके मन में होता है। परंतु धीरे-धीरे जैसे ही वे कक्षा और शिक्षक से परिचित होते हैं, स्कूल उनका दूसरा घर बन जाता है।

होते हैं, स्कूल उनका दूसरा घर बन जाता है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा केवल अक्षरों और संख्याओं को जानने तक सीमित नहीं है। यह वह समय होता है जब बच्चे अपने आसपास की दुनिया को समझना शुरू करते हैं। स्कूल में उन्हें व्यवहार, अनुशासन, सामाजिकता, सहभागिता, सहयोग, भावनाओं की अभिव्यक्ति और समस्याओं को सुलझाने जैसे गुणों की भी शिक्षा मिलती है। शिक्षक उन्हें न केवल किताबों का ज्ञान देते हैं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। एक बच्चा जब विद्यालय आता है तो वह केवल एक छात्र नहीं होता, बल्कि एक भविष्य का नागरिक होता है। प्रारंभिक शिक्षा उसकी सोच, आचरण, व्यवहार, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास की नींव होती है। यदि इस स्तर पर उसे उपयुक्त वातावरण, प्रेरणा और मार्गदर्शन मिले, तो उसका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। शिक्षक बच्चों के लिए पहले सामाजिक संरक्षक होते हैं। विशेषकर स्कूल के शुरुआती दिनों में बच्चों को अपने परिवार से दूर होकर अनजानी दुनिया में कदम रखना पड़ सकता है। ऐसे में शिक्षक की भूमिका केवल एक पढ़ाने वाले तक

सीमित नहीं रह जाती, बल्कि उन्हें एक मार्गदर्शक, मित्र, अभिभावक और सहायक की भूमिका भी निभानी होती है।

एक संवेदनशील शिक्षक बच्चे की शंकाओं को दूर कर उसे सहज बनाने का प्रयास करता है। वह उनके मन में सीखने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करता है, डर को खत्म करता है और सीखने को एक आनंदमय अनुभव बनाता है। शिक्षक अपने अनुभवों से बच्चों को न केवल पुस्तकीय ज्ञान देता है, बल्कि उन्हें सामाजिकता, सहयोग और सहिष्णुता भी सिखाता है। शिक्षा केवल स्कूल तक सीमित नहीं रह सकती। जब बच्चा घर से स्कूल आता है, तो उसे शिक्षा की यात्रा में निरंतर सहयोग की आवश्यकता होती है। अभिभावकों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक अवस्था में बच्चों को सीखने के लिए सकारात्मक वातावरण और प्रेरणा की आवश्यकता होती है, जो केवल शिक्षक ही नहीं, अभिभावक भी प्रदान करते हैं। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों के साथ संवाद बनाए रखें, उनकी रुचियों को समझें, उन्हें खुलकर सवाल पूछने दें और अपनी

भावनाएं व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही, संस्कारों की नींव भी घर से ही डलती है। इसलिए अभिभावकों को बच्चों में अनुशासन, आदर, प्रेम, करुणा और कर्तव्यबोध जैसे गुणों का भी बीजारोपण करना चाहिए विद्यालय केवल शिक्षकों और विद्यार्थियों की संस्था नहीं होती, वह समाज का भी एक अभिन्न अंग है। एक जागरूक समाज ही एक समर्थ और समर्पित शिक्षा व्यवस्था को जन्म दे सकता है। जब समुदाय स्कूल से जुड़ता है - चाहे वह स्थानीय स्वराज संस्थाएं हों, युवा स्वयंसेवक हों या वरिष्ठ नागरिक - तो बच्चों को जीवन से जुड़े अनुभव, प्रोत्साहन और संरक्षण मिलता है। आज देशभर में कई स्थानों पर विद्यालय समुदाय के सहयोग से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का कार्य कर रहे हैं। स्थानीय भाषा, संस्कृति, पारंपरिक खेल, कहानियाँ, गीत और लोकज्ञान को विद्यालय शिक्षा में सम्मिलित करने से बच्चों को जुड़ने से जोड़ना संभव होता है।

आज के बदलते समय में यह आवश्यक हो गया है कि शिक्षा प्रणाली बालकेंद्रित हो। प्रत्येक बच्चा भिन्न होता है - उसकी रुचि, समझने का तरीका, सीखने की गति

और भावनात्मक आवश्यकताएँ अलग-अलग होती हैं। ऐसे में शिक्षक और विद्यालय का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि हर बच्चे की रुचि और आवश्यकता के अनुसार लचीली और संवेदनशील शिक्षण पद्धति अपनानी चाहिए। स्कूल का पहला दिन केवल एक तिथि नहीं होती, वह एक नए जीवन अध्याय की शुरुआत होती है। बच्चों की किलकारियाँ से गुंजते विद्यालय केवल शैक्षणिक संस्थान नहीं होते, वे भविष्य की प्रयोगशालाएँ होते हैं जहाँ अगली पीढ़ी तैयार होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षक, अभिभावक और समाज मिलकर एक ऐसा माहौल तैयार करें जहाँ हर बच्चा न केवल ज्ञान प्राप्त करे, बल्कि आनंदित होकर सीखे, अपने भीतर की क्षमताओं को पहचाने और समाज के लिए एक सशक्त, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बन सके। स्कूल खुलने के इस मौसम में जब हर बच्चा अपनी नई आँखों में सपनों की चमक लिए कक्षा में प्रवेश करता है, तब हमारा कर्तव्य है कि हम उसके उन सपनों की उड़ान को सही दिशा दें - क्योंकि यही बच्चे कल देश का भविष्य गढ़ेंगे।

विकास के विरुद्ध विकास : नर्मदा की सच्ची परिक्रमा

फ़िल्म की कहानी मुख्यतः विकास, विस्थापन और पर्यावरण मुद्दों पर काम करने वाले एक ईमानदार इतालवी लेखक-निर्देशक अलेक्जेंड्रो उर्फ़ एलेक्स (मार्को लियोनार्डी) के माध्यम से खुलती होती है, जो अमृतलाल वेगड़ की नर्मदा पर लिखी प्रसिद्ध पुस्तक पढ़कर इस नदी के सौंदर्य और आत्मिक चेतना से गहरे प्रभावित होता है। वह नर्मदा की परिक्रमा और उससे जुड़ी आस्था पर एक फ़िल्म बनाना चाहता है। भारत रवाना होने से पहले वह अपने किशोर पुत्र को उसकी दादी के साथ रहने के लिए तैयार करता है — एक ऐसा पुत्र को जो माँ के बिना बड़ा हो रहा है।

तैयार करता है — एक ऐसे पुत्र को जो माँ के बिना बड़ा हो रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता रूपा (चित्रांगदा सिंह) की किताब से उसे नर्मदा नदी पर बन रहे बाँधों और उससे उत्पन्न डूब क्षेत्र की पर्यावरणीय और मानवीय त्रासदी का पता चलता है। रूपा फ़िल्म की सूत्रधार (एंकर) बनती है। टीम के साथ फ़िल्मांकन के दौरान एलेक्स की मुलाकात मंदिर के आसपास फेरीवाले किशोर 'लाला' (आर्यन बड़कुल) से होती है। होशियार लाला कई सारी भाषाएँ थोड़ी-थोड़ी बोलता है और एलेक्स को एक जादुई पत्थर दो हजार रुपये में बेच देता है। वो लाला से और बात करना चाहता है और जब एलेक्स उससे पूछता है कि वह यहाँ कैसे आया, तो लाला एक गहरी मुस्कान के साथ कहता है — 'हमरा नसीब (मेरा दुर्भाग्य)।'

रूपा से इस वाक्य का अर्थ समझकर एलेक्स के भीतर एक नई संवेदना जन्म लेती है। एलेक्स विकास के नाम पर अबोध, सरल और सहनशील ग्रामीणों के जबरन विस्थापन से व्यथित होता है और वह इस अन्याय पर अपना आक्रोश ज़ाहिर करता है। शाम को शूटिंग के बाद चर्चा के दौरान एलेक्स रूपा और अपने कैमरामैन बिजोंय से लाला का ज़िक्र करता



है और उसकी फोटो दिखाता है। बिजोंय लाला की बोलती आँखों से प्रभावित होता है। एलेक्स को वहाँ एक पुरातन महक की अनुभूति होती है। पर्यावरण सजग एलेक्स अब लाला को केंद्र में रखकर विस्थापन की कहानी कहना चाहता है।

शुरू में रूपा इस नई दिशा का विरोध करती है — उसे लगता है कि एलेक्स आस्था की कथा को 'पीड़ा' में बदलकर बेचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाद में वह सहमत होती है और लाला को दस-बारह दिन के लिए फ़िल्म में भाग लेने को राज़ी कर लेती है। यहीं से शुरू होती है विस्थापन की उस अनकही त्रासदी की मार्मिक कथा, जो आज भी हमारी नदियों के किनारे ख़ामोश बह रही है।

श्रद्धाभाव से की जा रही एक नदी की परिक्रमा का फ़िल्मांकन अचानक एक सामाजिक-राजनीतिक यथार्थ — डूब, विस्थापन और विखंडन — में कैसे तब्दील हो जाता है, यह अनुभव अत्यंत प्रभावशाली है। फ़िल्म 'विकास' की उस राजनीति को भी दिखाती है जिसने नर्मदा घाटी में बसे हजारों लोगों को उखाड़ फेंका और पर्यावरण को अप्रुणीय क्षति पहुँचाई। रूपा का एक संवाद फ़िल्म के केंद्रीय भाव को बहुत मार्मिकता से कहता है — 'विकास ही विकास के विरुद्ध था।'

नर्मदा नदी और नर्मदा घाटी के अत्यंत सुंदर दृश्य और बाढ़-डूब के उतने ही विहंगम दृश्यों को बेहद खूबसूरती से फिल्माया गया है। फ़िल्म में भारतीय और इतालवी लोकसंगीत का प्रयोग, उनका संपादन और संयोजन फ़िल्म की आत्मा में रच-बस जाते हैं। साउंड डिज़ाइन एक और सशक्त पहलू है फ़िल्म का। यह सब मिलकर फ़िल्म को एक वृत्तचित्रनुमा सिनेमाई पूर्ण अनुभव बनाते हैं। फ़िल्म की शूटिंग मुख्यतः अमरकंटक, मंडला, भेड़ाघाट, बड़वानी, मधेश्वर और ओंकारेश्वर में हुई है। इसके अलावा इटली में नेपल्स भी रमणीक चित्रित हुआ है।

आर्यन बड़कुल द्वारा निभाया गया 'लाला' मासूमियत और चपलता का अनेखा संगम है। एलेक्स जब अपने बेटे की तुलना लाला से करता है — 'दोनों के दर्द हैं - एक मातृत्व विहीन है, दूसरा मातृभूमि विहीन' — तो वह सिर्फ़ संवाद नहीं, एक युगबोध बन जाता है। लाला की घर लौटने की आस में उसका कहना कि - 'माँ से कहूँगा दाल-चावल के साथ अपनी वाली चटनी खिलाओ, बहुत भूख लगी है कई दिनों से' — दर्शक की आँखें नम कर देती है।

मार्को लियोनार्डो इटली के जानेमाने अभिनेता हैं। वो एलेक्स के किरदार में पूरी गहराई के साथ उतरते हैं। चित्रांगदा सिंह, अपने ग्लैमर से इतर, बेहद प्रभावशाली और सच्ची लगती हैं — विशेषतः लाला के साथ उनके संवादों में। फ़िल्म की दृश्य भाषा जितनी प्रामाणिक और संवेदनशील है, उतनी ही कमी भाषिक स्तर पर महसूस होती है। मंडला और निमाड़ अंचल की विशिष्ट बोलियों — विशेषकर निमाड़ी के लहजे और उच्चारण — का न होना थोड़ा खटका नहीं, बल्कि एक गहन अंतर्थाड़ा है। परंपरा, श्रद्धा, सवाल और स्मृति के बीच बहती यह कथा माँ नर्मदा के बहाने हमारे समय के सबसे कठिन और असहज प्रश्नों से साक्षात्कार कराती है — और दर्शक को भीतर तक छू जाने वाला एक नया अनुभव सौंप जाती है।

संक्षिप्तसमाचार

धरती आबा अभियान से जनजातीय वर्ग तक सुगमता से पहुंच रहा शासन की योजनाओं तथा सेवाओं का लाभ

रायसेन (निप्र)। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय वर्ग के लोगों के पास, उनके घर पहुंचकर शासन की अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं तथा सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। इन योजनाओं का लाभ पाकर जनजातीय वर्ग के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, आर्थिक उन्नति हुई है। रायसेन जिले के सिलवानी तहसील के ग्राम डोकरी बमनई निवासी संतोष कुमार भी उन हितग्राहियों में शामिल हैं जिन्हें धरती आबा अभियान के तहत गांव में शिविर लगाकर योजनाओं का लाभ दिया गया है। हितग्राही संतोष कुमार को धरती आबा अभियान अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, विद्युत कनेक्शन, सम्बल कार्ड, खाद्यान्न पात्रता पची, उज्ज्वला योजना, सहित अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है। धरती आबा अभियान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हुए संतोष कुमार बताते है कि अभियान के तहत योजनाओं का लाभ मिलने से उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है तथा वह और उनका परिवार खुशहाल है।

किसानों के खेतों में उगवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर निर्माण एवं खेत तालाब बने

विदिशा (निप्र)। जल गंगा संवर्धन अभियान विदिशा जिले में वृद्धि स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के खेतों में दुग्वेल रिचार्ज स्ट्रक्चर और खेत तालाब का निर्माण कराया गया है किसानों के खेतों में इस तरह की संरचना स्थापित हो जाने से सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी इस वर्षा ऋतु में पानी एकत्रित होता और वह किसानों की फसलों में सिंचाई के लिए उपयोग होगा। किसानों के खेतों में रिचार्ज स्ट्रक्चर निर्माण और खेत तालाब बन जाने से अब इन किसानों को सुखे की स्थिति से निपटना नहीं पड़ेगा। भूजल स्तर में सुधार होगा और सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सकेगा। ये संरचनाएँ वर्षा के जल को भूजल में रिसने देती हैं। जिससे पानी की कमी और सूखे की समस्या की संभावना बहुत कम हो जाती है। जनपद पंचायत बासीदा की ग्राम पंचायत पैरवासा में निवासरत किसान श्री अयुब खान के खेत में जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत डवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर का कार्य किया गया है। श्री तरह गंजबासीदा की ही ग्राम पंचायत अंबानगर के किसान श्री मनोज चिढ़ार के खेत में तालाब का निर्माण कराया गया है जो उनके कृषि कार्य में सहयोग प्रदान करेगा। दोनों किसानों ने जल गंगा संवर्धन अभियान के क्रियान्वयन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने पीएम आवास के हितग्राहियों को साँपी नवनिर्मित मकान की चाबी

सीहोर (निप्र)। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं राज्यस् मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने इछवर के ग्राम कांकरखेड़ा पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मकान की चाबी सौंपकर उनका ग्रह प्रवेश कराया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार प्रत्येक गरीब के पक्के घर के सपने को साकार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने आवास योजना की सूची में नाम जुड़ने पर श्रीमती पार्वती देवी सहित अन्य हितग्राहितयों को बधाई पत्र भी प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्री नरेश मेवाड़ा, विधायक श्री सुदेश राय, नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रिंस राठौर, श्री रवि मालवीय, श्री विष्णु वर्मा, जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

अब वर्षा जल के आभाव में भी फसलों की सिंचाई होगी आसान

■ श्री रामनिवास सांखला को मिली खेत तालाब की सोगात

हरदा (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अनुवाई में प्रदेश भर में जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से सरकार और समाज के द्वारा पुरानी जल संरचनाओं में जल भरण, जल के प्रबंधन तथा नई जल संरचनाओं का निर्माण का कार्य जा रहा है। जल के बिना जीवन की परिकल्पना शून्य है और इसके बिना न तो कृषि संभव है, न ही उद्योग और न ही हमारी दैनिक आवश्यकताएँ पूरी हो सकती हैं। जल का संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है। हरदा जिले की जनपद पंचायत हरदा अंतर्गत ग्राम कचबेड़ी निवासी किसान रामनिवास सांखला को जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नवीन खेत तालाब का उपहार मिला। खेत तालाब बनने से अब रामनिवास सांखला को वर्षा के अंतराल के दौरान फसल की सिंचाई के लिए वर्षा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। खेत तालाब का निर्माण होने से रामनिवास प्रफुल्लित है। रामनिवास कहते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं फसलों की सिंचाई या अन्य कार्य के लिए सिंचाई का साधन जुटा सकूँ। खेती का कार्य पूरी तरह वर्षा जल पर निर्भर था, जिस वर्ष अच्छी नहीं होती थी तो उस वर्ष सिंचाई का साधन न होने के कारण फसलें सूख जाती थी। खेत तालाब का निर्माण हो जाने से अब मुझे इस चिंता से मुक्ति मिल गई है। इसके लिए मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।

राजधानी आसपास

स्व-सहायता समूह से मिली नई राह, श्रीमती अंगूरी अहिरवार बनीं आत्मनिर्भरता की मिसाल



नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम जिले के ग्राम भटगांव की रहने वाली अंगूरी अहिरवार आज ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। एक समय था जब उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, लेकिन आज वे न केवल आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी सशक्त बनाने का कार्य कर रही हैं। श्रीमती अंगूरी

अहिरवारका जीवन बदलने की शुरुआत 18 फरवरी 2019 को हुई, जब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्राम में महिला समूहों के गठन का कार्य किया गया। अंगूरी अहिरवार ने साईराम स्व-सहायता समूह से जुड़कर अपने जीवन को नई दिशा दी। समूह से जुड़ने के बाद दीदी को आजीविका गतिविधियों की जानकारी प्राप्त हुई।

उन्होंने ग्राम में ही एक कॉमन सर्विस सेंटर शुरू किया, जिससे न केवल उनकी आमदनी बढ़ी बल्कि ग्रामवासियों को भी ऑनलाईन सेवाओं का लाभ मिलने लगा। अब वृद्धजनों को पेंशन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, बैंकिंग कार्य भी ग्राम में ही संभव हो गए हैं। इतना ही नहीं, अंगूरी अहिरवार ने मछली पालन की गतिविधि भी शुरू की जिससे उनकी आय में और वृद्धि हुई। विभिन्न संस्थाओं से मार्गदर्शन प्राप्त कर उन्होंने इस क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया। वर्तमान में अंगूरी अहिरवार की मासिक आय लगभग 13,000 तक पहुंच गई है - जिसमें सीएससीसेंटर से 5,000 एवं मछली पालन से 8 हजार रुपए की आय शामिल है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत उन्हें 1250 रुपए मासिक सम्मान राशि भी प्राप्त हो रही है। श्रीमती अंगूरी अहिरवार बताती हैं कि उन्होंने अपने समूह और परिवार के सहयोग से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल रही हैं। अब वे अन्य महिलाओं को भी स्व-सहायता समूहों में शामिल होने के लिए प्रेरित करती हूं। आज श्रीमती अंगूरी न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी सशक्त हुई हैं। वे समूह और ग्राम संगठन की बैठकों में सक्रिय भूमिका निभाकर महिलाओं को विभिन्न सामाजिक विषयों पर जागरूक करने का कार्य कर रही हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं साईराम स्व-सहायता समूह के सहयोग से अंगूरी अहिरवार ने जो सफलता प्राप्त की है, वह निश्चित ही अन्य ग्रामीण महिलाओं के लिए एक प्रेरक उदाहरण है।

खनिज विभाग की बड़ी कार्यवाही: मुरुम और गिट्टी का अवैध परिवहन करते 4 डम्पर किए जप्त

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स की बैठक में वन, राजस्व, पुलिस, परिवहन एवं खनिज विभाग को खनिज संपदा के अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन को रोकने के दिशा-निर्देश दिए थे। इसी अनुक्रम में खनिज विभाग द्वारा शनिवार को मुरुम और गिट्टी का अवैध परिवहन करते 4 डम्पर तथा ग्राम चापड़ा रैयत में खनिज रेत के अवैध भंडारण पर बड़ी कार्यवाही की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खनिज अमला द्वारा 28 जून को तहसील बैतूल अन्तर्गत आठनेर रोड पर ग्राम सूरगांव के समीप 4 डम्पर क्रमशः बीआर 31 जीए 3604, एमपी 04 एचई 5410, एमएच 12 डब्ल्यूजे 9371 एवं एमएच 12 डब्ल्यूजे 9471 को खनिज मुरुम और गिट्टी का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर जप्त कर पुलिस थाना गंज बैतूल की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है।

भोगा रेत खदान से बिना अनुमति के भंडारित की गई थी रेत : इसी प्रकार खनिज एवं राजस्व अमले द्वारा संयुक्त रूप से आकस्मिक निरीक्षण कर तहसील शाहपुर ग्राम चापड़ा रैयत स्थित निजी भूमि खसरा क्रमांक 6/2/2 रकबा 0.500 हेक्टेयर क्षेत्र के अंश भाग पर निर्माणाधीन होटल के पीछे खनिज रेत का अवैध भण्डारण पाये जाने पर अवैध

भण्डारणकर्ता पर कार्यवाही की गई। जांच के दौरान पाया गया कि उक्त खनिज रेत को भोगा रेत खदान से ट्रैक्टर-ट्रालियों से परिवहन करके बिना अनुमति के अवैध रूप से भण्डारित की गई थी, जिसकी कुल मात्रा 180 घन मीटर पाई गई। मौके पर अवैध भण्डारणकर्ता द्वारा उक्त खनिज रेत के संबंध में किसी प्रकार की कोई अनुमति एवं रॉयल्टी के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

मौके पर सहायक खनि अधिकारी बैतूल द्वारा प्रभारी खनि सर्वयर, हल्का पटवारी एवं अन्य पंचगणों की उपस्थिति में पंचनामा, जप्ती पत्रक तैयार कर अवैध भण्डारणकर्ता के विरुद्ध खनिज नियमों के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। गौरतलब है, कि खनिज विभाग द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बैतूल के निर्देशों में लगातार आकस्मिक निरीक्षण कर खनिजों के अवैध परिवहन, उत्खनन, भण्डारण पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। उक्त सभी अवैध परिवहनकर्ताओं एवं भण्डारणकर्ता के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण नियम 2022 के तहत प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड प्रस्तावित कर प्रकरण माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभी तक किया जा चुका है 5358 हितग्राहियों को लाभान्वित

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार जनजातीय आबादी के लिए समान अवसरों का सुजन, सामाजिक-आर्थिक स्तर का विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका के क्षेत्र में ठोस प्रगति के उद्देश्य से जिले में 15 जून से 15 जुलाई तक धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सीहोर जिले के चिन्हित 80 गांवों में अब 15 जुलाई तक दिनांकवार शिविर लगाए जा रहे हैं। अभियान के तहत ग्रामों में ग्राम सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं। अभियान के तहत 29 जून को चिन्हित गांवों में शिविर लगाकर 179 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

अभियान के तहत जिले के चिन्हित गांवों में लगाए जा रहे शिविरों में अभी तक 5358 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने इस अभियान के तहत चिन्हित किए गए सीहोर जिले के 80 गांवों के जनजातीय समुदाय के नागरिकों से अभियान के तहत दिनांकवार लगने वाले शिविरों में उपस्थित होने और योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ लेने की अपील की है। उन्होंने अपील की है कि सभी पात्र हितग्राही शिविरों में उपस्थित हों और पात्रतानुसार शासन की योजनाओं और सेवाओं का लाभ लें, ताकि



जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों का भी निरंतर विकास हो सके और कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। शिविरों में हितग्राहियों का आयुष्मान भारत योजना, केसीसी योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मातृवंदना योजना, बाल आशीर्वाद योजना, तैत्पता संग्रहण एवं बोनस योजना, एकलव्य योजना, दिव्यांग पेंशन प्रोत्साहन योजना, कल्याणी पेंशन योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, विश्वकर्मा योजना, पीएम सूर्यघर योजना, घरेलू

कनेक्शन सब्सिडी योजना, पांच रूपये में नवीन विद्युत कनेक्शन योजना, पीएम आवास योजना सहित अनेक योजनाओं के लिए पंजीयन किया जा रहा है और इन योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इसके साथ ही अभियान के तहत सभी पात्र हितग्राहियों का आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, समग्र आईडी, ई-केवायसी, जाति प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रोफाइल पंजीयन एवं बैंक खाता खोलना सहित अनेक सेवाओं के लिए पंजीयन भी किया जा रहा है।

प्रधान जिला न्यायाधीश सहित न्यायाधीश गणों और अधिकारियों ने किया पौधारोपण

पौधारोपण कार्यक्रम में रोपे गए लगभग 500 पौधे

जिला न्यायालय भवन सीहोर की रिक्त भूमि पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रकाश चंद्र आर्य एवं अन्य न्यायाधीशगणों में ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश श्री प्रकाश चंद्र आर्य ने कहा कि पेड़ हमारे जीवन का आधार हैं। वर्तमान में मानव द्वारा पेड़ों का अत्यधिक दोहन किया गया है जिस कारण मानव जीवन पर जलवायु परिवर्तन का संकट मंडराने लगा है।

हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि प्रकृति को फिर से हरा भरा बनाया जा सके। कार्यक्रम में न्यायालय के सभी न्यायाधीशगणों, अधिवक्तागण, लीगल एड डिफेंस कार्टिसिल्स तथा कर्मचारीगण द्वारा लगभग 500 पौधे रोपे गए। पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाए हैं ताकि पौधों की देखभाल भी सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम में प्रधान



न्याय संवाद एक नई पहल के तहत जिला न्यायालय में सत्र आयोजित

सीहोर (निप्र)। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीहोर श्री प्रकाश चंद्र आर्य के निर्देशानुसार सीहोर जिला न्यायालय परिसर में स्थित अधिवक्ता संघ के सभाकक्ष में न्याय संवाद एक नई पहल के तहत सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश श्री प्रकाश चंद्र आर्य ने परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही न्याय संवाद के अंतर्गत होने वाली अनौपचारिक चर्चा को उल्लेखनीय पहल बताते हुये युवा अधिवक्ताओं के लिए पहल को अत्यधिक लाभकारी बताया। इस दौरान विशेष न्यायाधीश श्री हेमंत जोशी ने स्थानी लोक अदालत लोकोपयोगी विषय पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

सचिव श्रीमती स्वन्श्री सिंह ने पीडित प्रतिकर योजना एवं न्याय संवाद एक नई पहल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत प्रतिमाह अधिवक्तागण एवं न्यायाधीशगण मिलकर नियत कानूनी विषय पर उसके प्रावधानों, कठिनाईयें तथा समाधानों पर विस्तार से चर्चा करते हैं, जो कि सभी के लिए लाभकारी है और पक्षकारों को भी इससे फायदा हो रहा है। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती विनीता गुप्ता, न्यायाधीश श्री दीपेन्द्र मालू, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष श्री राधेश्याम यादव, अभिभाषक संघ सचिव श्री राजेश वर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जोशान खान सहित अन्य अधिकारी, पैनल अधिवक्ता, अधिवक्तागण लीगल एड डिफेंस कार्टिसिल्स उपस्थित थे।

उमरवानी के कृषक अर्जुन ने रेटावेटर से खेती को बनाया लाभ का व्यवसाय

नरवाई जलाने की जगह अपनाई तकनीक, बड़ी मिट्टी की उर्वरता और फसल की गुणवत्ता

बैतूल (निप्र)। यदि इच्छाशक्ति हो और सरकार की योजनाओं का सही उपयोग किया जाए, तो खेती को लाभकारी व्यवसाय में बदला जा सकता है। बैतूल जिले के ग्राम उमरवानी के किसान श्री अर्जुन धुर्वे ने कृषि यंत्रीकरण की दिशा में एक प्रेरणादायी कदम उठाते हुए आधुनिक खेती को अपनाया है। कृषि अभियांत्रिकी विभाग के सहयोग से उन्होंने एक लाख रुपये मूल्य का रेटावेटर खरीदा, जिसमें उन्हें 46 हजार 800 रुपये का अनुदान मिला।

यह उपकरण अब उनकी खेती की दिशा और दशा दोनों बदल रहा है। रेटावेटर के माध्यम से कृषक श्री धुर्वे अब गेहूं की कटाई के बाद खेत में बची नरवाई को जलाने के बजाय उसे बारीकी से काटकर मिट्टी में मिला देते हैं। इस तकनीक से न सिर्फ खेत की मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ी है, बल्कि फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में भी सकारात्मक सुधार देखा गया है।



अन्य किसानों के लिए भी बने मिसाल

कृषि विभाग के अधिकारियों ने श्री धुर्वे की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि अनुदान योजना के माध्यम से सरकार किसानों को आधुनिक उपकरणों की खरीद में सहायता प्रदान कर रही है, जिससे खेती में लागत घटे और लाभ बढ़े। कृषक श्री धुर्वे ने बताया कि पहले हम नरवाई को जलाने के लिए मजबूर थे, जिससे न केवल मिट्टी की सेहत बिगड़ती थी, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान होता था। अब रेटावेटर से वही नरवाई मिट्टी में मिलकर प्राकृतिक खाद बन जाती है, जिससे फसल अच्छी होती है और लागत भी कम आती है। जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है।

जिले में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता, किसानों को उर्वरक मिलने में परेशानी न हो : कलेक्टर श्री सूर्यवंशी

बैतूल (निप्र)। खरीफ सीजन में बुवाई के लिए जिले में खाद की उपलब्धता पर्याप्त है। किसानों को उर्वरक मिलने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। यह निर्देश कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने उप संचालक कृषि सहित सभी एसडीओ कृषि, आरएईओ और एसीटीओ को दिए। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले में खाद की उपलब्धता और वितरण की ब्लॉकवार विस्तार से समीक्षा की। उपसंचालक कृषि ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है। वर्तमान में 8000 मीट्रिक टन उर्वरक जिले में उपलब्ध हैं। 30 जून तक जिले को एक और उर्वरक की रैक प्राप्त होगी। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने निर्देशित किया कि सभी एसडीओ अपने क्षेत्र में समितियां और निजी खाद की

दुकानों का निरीक्षण कर स्टॉक वेरिफिकेशन सुनिश्चित कराएं। खाद का निर्धारित दर से अधिक विक्रय करने वाले या अनियमितता करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जिन समितियों और खाद की दुकानों में उर्वरक की उपलब्धता है उसके बारे में किसानों को जानकारी दी जाए। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बैठक में सभी एसडीओ कृषि से खाद की उपलब्धता और वितरण की जानकारी ली। साथ ही निजी दुकानों और समितियों के उनके द्वारा किए गए निरीक्षण में पाई गई कमियों के बारे में भी पूछा। उन्होंने संतोष जनाक जवाब नहीं देने और भैंसदेही में खाद वितरण के लिए उचित कदम नहीं उठाने पर एसडीओ कृषि भैंसदेही की एक वेतन वृद्धि रोके जाने का कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

तीन किसानों को पीएमकेएसवाय योजना में रिसंक्लर सिस्टम प्रदान किये

विदिशा (निप्र)। जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जिले में जल स्रोतों को संवर्धन के साथ-साथ पानी की बचत करने के उद्देश्य से किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा भी गतिविधियां आयोजित की गईं और कृषकों को फसल में पानी छिड़काव के लिए पीएमकेएसवाय के तहत रिसंक्लर सिस्टम प्रदान किए गए हैं, जिसमें विदिशा जिले के ग्राम गढ़ला निवासी किसान श्री सरदार सिंह, ग्राम शेरापुर निवासी श्री समीर खान और ग्राम सहजाखेड़ी के समीर खान लाभान्वित हुए हैं। इन तीनों किसानों को कृषि विभाग द्वारा रिसंक्लर सिस्टम प्रदान किए गए हैं किसानों का कहना है कि यह सिस्टम प्रणाली के माध्यम से उनके खेतों में वह पानी का छिड़काव कर सकेंगे जो उनके लिए उपयोगी साबित होगा।

